दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 गोमांस फेंकने का धंधा बंद होना चाहिए, अन्यथा बदले की कार्रवाई हो सकती है

6 आपातकाल : आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

7 मोदी की पार्टी में शामिल होने का मेरा कोई संकेत नहीं : थरूर

फर्स्ट टेक

सीडीएस चौहान तीनों सेनाओं को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान को संयुक्त निर्देश एवं संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। यह उस पुरानी प्रणाली में किया गया परिवर्तन है, जिसमें दो या अधिक सेनाओं से संबंधित निर्देश/आदेश प्रत्येक सेना द्वारा अलग-अलग जारी किए जाते थे। यह कदम सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्तता के लिए 'थिएटराइजेशन मॉडल' को लागू करने के सरकार के प्रयासों के बीच उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संयुक्त निर्देशों और संयुक्त आदेशों के 'अनुमोदन, प्रकाशन और क्रमांकन' पर पहला संयुक्त आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

जापान ने पहली बार किया मिसाइल परीक्षण

टोक्यो/एपी। जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण किया है। देश की सेना ने मंगलवार को यह घोषणा की। जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के 'शिजुनाई एंटी-एयर फायरिंग रेंज' में 'टाइप-88' मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अधिकारियों ने बताया कि 'ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स' की पहली 'आर्टिलरी ब्रिगेड' के अभ्यास में लगभग 300 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने होक्काइडो के दक्षिणी तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर जहाज पर गोलीबारी की थी, जिसमें कोई भी चालक नहीं था। उन्होंने बताया कि अधिकारी अभी परीक्षण के परिणामों की जांच कर रहे हैं। जापान, चीन के प्रतिरोध के लिए जवाबी हमला करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है।

इंडोनेशिया में आधे टन से अधिक मादक पदार्थ जब्त, 285 लोग गिरफ्तार

जकार्ता (इंडोनेशिया)/एपी। इंडोनेशिया में दो महीने की कार्रवाई के दौरान 29 महिलाओं और सात विदेशियों समेत 285 लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से आधे टन से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इंडोनेशिया में मादक पदार्थों से संबंधित सख्त कानून हैं तथा दोषी तस्करों को कभी-कभी गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। इसके बावजूद यह दक्षिण पूर्व एशिया में मादक पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख केंद्र है।

25-06-2025 सूर्यास्त 6:49 बजे | 26-06-2025 सूर्योदय 5:56 बजे

BSE	NSE
82,055.11	25,044.35
(+158.32)	(+72.45)

सोना	चांदी
10,216 रु.	107,267 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड से बचें : एनएसए डोभाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद का कोई भी कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है।

बीजिंग/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड अपनाने से बचने का आह्वान किया और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्यों से सीमा पार आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों और वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।

इसे व्यापक रूप से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग के रूप में देखा जा रहा है।

डोभाल ने बीजिंग में एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

एनएसए ने कहा कि भारत, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), अलकायदा, आईएसआईएस और इसके सहयोगी जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित है।

डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद का कोई भी कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है।

एनएसए ने एससीओ सदस्यों से सीमापार आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने तथा उन्हें न्याय के दायरे में लाने में मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और आतंकवादियों को भारत में हमले करने से रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत : प्रधानमंत्री मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ 'ऑपरेशन सिंदूर' ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है और उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित हों, उठाती है।

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है और उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित हों, उठाती है।

आध्यात्मिक संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत के शताब्दी समारोह के अवसर पर मोदी ने देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत में निर्मित हथियारों ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने कहा , हमने दिखाया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आध्यात्मिक संत श्री नारायण गुरु के आदर्शों पर काम किया है, जो भेदभाव से मुक्त मजबूत भारत चाहते थे।

मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उनकी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में भारत को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो रही है और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों के संदर्भ में कहा कि भारतीय सेना ने 22 मिनट में भारत में निर्मित हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भविष्य में भारत में निर्मित हथियारों को दुनिया भर में सराहा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आवास, पेयजल और स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनसे समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, इससे पहले की तुलना में अधिक संख्या में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान खोले गए हैं।

मोदी ने कहा कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा , नारायण गुरु ने सभी तरह के भेदभाव से मुक्त समाज की परिकल्पना की थी। आज, देश भेदभाव की प्रत्येक संभावना को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'स्किल इंडिया' जैसे मिशन युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक कम से कम छह तेजस विमान मिल जाएंगे

एचएएल के प्रमुख डी के सुनील ने यह जानकारी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ जीई एयरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति नहीं हुई है। जीई को 2023 में इंजन की आपूर्ति करनी थी। अब तक, केवल एक इंजन मिला है।

▪ जीई की ओर से देरी शुरू में कोविड महामारी के दौरान उत्पादन में विलंब और उसके बाद कंपनी से कई वरिष्ठ इंजीनियरों के चले जाने के कारण हुई, जिससे आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न हुई।

बेंगलूरु/नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक कम से कम आधा दर्जन हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मिल जाएंगे। इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के प्रमुख ने यह जानकारी दी। एलसीए तेजस के एमके-1ए संस्करण की आपूर्ति में देरी का मामला वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने हाल ही में उठाया था, जिसके बाद यह बड़ा मुद्दा बन गया था। एचएएल के प्रमुख ने कहा है कि तेजस की आपूर्ति में हुई देरी के लिए जीई एयरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति में विलंब जिम्मेदार है। एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डी के सुनील ने कहा कि यह देरी केवल अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस द्वारा समय पर एफ404 इंजन की आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण हुई।

एचएएल प्रमुख ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि जीई एयरोस्पेस द्वारा चालू वित्त वर्ष में 12 इंजन की आपूर्ति किये जाने की उम्मीद है। इससे भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में आसानी होगी। उन्होंने कहा, ''हर कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता (ही) है। दुर्भाग्य से, एलसीए मार्क-1ए के मामले में (भी ऐसा ही हुआ है), हमने विमान बना लिये हैं। आज की तारीख में, हमारे पास छह विमान तैयार हैं।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन जीई एयरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति नहीं हुई है। उसे (जीई को) 2023 में इंजन की आपूर्ति करनी थी। अब तक, हमें केवल एक इंजन मिला है।'' जीई की ओर से देरी शुरू में कोविड महामारी के दौरान उत्पादन में विलंब और उसके बाद कंपनी से कई वरिष्ठ इंजीनियरों के चले जाने के कारण हुई, जिससे आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न हुई। सुनील के अनुसार, जीई एयरोस्पेस के साथ तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और एचएएल को मार्च 2026 तक 12 जेट इंजन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ''मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आज की तारीख में छह विमान तैयार हैं। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है।

एएआईबी कर रहा है अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच

पुणे/भाषा। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि गत 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एअर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) इसकी जांच कर रहा है। नायडू ने ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजे जाने संबंधी अटकलों को खारिज कर दिया। गत 12 जून को लंदन के लिए रवाना होने वाला एअर इंडिया का विमान दोपहर में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के एक छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों समेत 270 लोगों की मौत हो गई थी। एअर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान का ब्लैक बॉक्स 13 जून को घटनास्थल से बरामद किया गया था। ब्लैक बॉक्स एक छोटा उपकरण होता है जो उड़ान के दौरान विमान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है। यह विमान दुर्घटनाओं की जांच में मदद करता है।

भारत 'टैरिफ किंग' नहीं, प्रभावी दर बहुत कम : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि भारत 'टैरिफ किंग' (अत्यधिक शुल्क लगाने वाला देश) है। उन्होंने कहा कि उनके ताजा बजट में शुल्क दरों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई है और प्रभावी दर बहुत कम है। उन्होंने कहा , जो लोग अब भी अमेरिका में की गई टिप्पणी पर भरोसा करते हैं कि भारत 'टैरिफ किंग' हो सकता है... मैं चाहती हूं कि वे दो बातें याद रखें। हमारी शासन व्यवस्था को देखते हुए हमें शुल्क दर पर निर्णय लेने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए... एक निश्चित स्तर तक जाने की अनुमति, लेकिन प्रभावी रूप से हमारी दरें बहुत निचले स्तर पर हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार भारत को बहुत अधिक शुल्क वाला देश बताया है। ट्रंप ने भारत को ''टैरिफ किंग'' और शुल्क व्यवस्था का ''बड़ा दुरुपयोग करने वाला'' कहा था।

वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए 2025-26 के बजट में शुल्क दरों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई।

सीतारमण ने फरवरी के बजट में सात शुल्क दरें हटा दी थीं। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात शुल्क दरों के अलावा थीं।

ईरान, इजराइल दोनों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया : ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ मंगलवार को यह संघर्ष विराम उस समय टूट गया, जब इजराइल ने ईरान पर संघर्ष विराम लागू होने के बाद उसके हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागने का आरोप लगाया तथा जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प जताया।

वाशिंगटन/एपी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए मंगलवार की समय-सीमा समाप्त होने के बाद हमले करके संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है।

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम को बनाए रखने की कोशिश कर रहे ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी कि वह अपने पायलटों को वापस बुला ले।

यह बात 'ट्रुथ सोशल' पर मंगलवार को एक पोस्ट में कही गई।

हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने लगातार हो रहे हमलों पर निराशा व्यक्त की।

ट्रंप ने कहा, उन्होंने इसका उल्लंघन किया, लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, मैं इजराइल से खुश नहीं हूं।

लगभग उसी समय, उन्होंने एक 'ट्रुथ' पोस्ट में कहा, इजराइल। उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो, तो यह एक बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलटों को वापस बुलाओ!

मंगलवार को यह संघर्ष विराम उस समय टूट गया, जब इजराइल ने ईरान पर संघर्ष विराम लागू होने के बाद उसके हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागने का आरोप लगाया तथा जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प जताया।

सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान की सेना ने इजराइल पर हमला करने से इनकार किया है - लेकिन मध्याह्न के समय उत्तरी इजराइल में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं और सायरन बजने लगे, तथा एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने कहा कि दो ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया।

पाकिस्तान सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करेगा : प्रधानमंत्री शरीफ

इस्लामाबाद/भाषा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई और सऊदी अरब तथा कतर के राजनयिकों के साथ पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात पर चर्चा की।

यहां एक सरकारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के लिए खतरा बने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री शरीफ ने सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल-ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धविराम की घोषणा की थी। आधिकारिक बयान के अनुसार, ईरानी नेता मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने के महत्व पर जोर दिया।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि

हमारे समूह के बनाए ड्रोन ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में अग्रणी भूमिका निभायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उनके समूह द्वारा बनाए गए ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

'ऑपरेशन सिंदूर' पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब के तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया था।

अपने समूह की वार्षिक आम बैठक में अदाणी ने कहा , ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने कर दिखाया।

'अदाणी डिफेंस' द्वारा निर्मित हथियारों ने सटीक हमले किए, जबकि इसकी ड्रोन रोधी इकाइयों ने जवाबी खतरों से भारतीय संपत्तियों की रक्षा की। उन्होंने कहा , हमारे ड्रोन आसमान में नजर रखने वाली आंख के साथ-साथ हमले की तलवार भी बन गए हैं और हमारी ड्रोन रोधी प्रणालियों ने हमारे बलों और नागरिकों की सुरक्षा में मदद की है।

'अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज' (अडानी डिफेंस की 26 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी) और इजराइल की 'एल्बिट सिस्टम्स' की साझेदारी में विकसित स्काईस्ट्राइकर हथियार या कामिकेज़ ड्रोन 5-10 किलोग्राम के हथियार ले जा सकते हैं, 100 किलोमीटर तक की कम ऊंचाई पर चुपचाप उड़ सकते हैं, और लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकते हैं।

अदाणी ने कहा , जैसा कि मेरा हमेशा से मानना है कि हम सुरक्षित क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। हम वहां काम करते हैं, जहां यह जरूरी है, जहां भारत को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है।

अदाणी ने वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम किया। उन्होंने कहा , इस वर्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारे बहादुर पुरुष और महिलाएं वर्दी में डटे रहे। प्रसिद्धि के लिए नहीं, पदकों के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए। उनके साहस ने हमें याद दिलाया कि शांति कभी मुफ़्त नहीं मिलती, इसे अर्जित किया जाता है। और सपने देखने, उन्हें पूरा करने और नेतृत्व करने की स्वतंत्रता हमारी सुरक्षा करने वाले लोगों के कंधों पर मजबूती से टिकी है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति के महत्व को समझता है। उन्होंने कहा , लेकिन अगर कोई उसे खतरे में डालने की कोशिश करता है, तो भारत उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा कि पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक अस्थिरता से लेकर पश्चिम में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद दूरदर्शी नीति निर्माण और साहसिक राष्ट्रीय इरादे के कारण भारत विकास के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सभी मगन हैं

व्यापारी बस सोच रहा है,
कैसे आए जी भर नोट।
ढूंढ रहे हैं सभी क्रिकेटर,
आइपीएल में लम्बे शाट।
पार्टी वाले नेतागण सब,
पकड़ रहे हैं वोटर वोट।
आम आदमी राम भरोसे,
गुमसुम बैठा खा कर चोट।।

सरकारों को संसदीय समितियों की रिपोर्ट को रचनात्मक तरीके से लेना चाहिए: बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सरकारों को संसदीय समितियों की रिपोर्ट को उनके कामकाज की आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि रचनात्मक तरीके से लेना चाहिए।

बिरला ने संसद और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विचार-विमर्श के दौरान एक मजबूत दृष्टिकोण सामने आया कि संसदीय समितियां सरकार के खिलाफ काम नहीं करती हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।

उनका कहना था , मेरा मानना है कि सरकारों को संसदीय समितियों की रिपोर्ट को भी रचनात्मक तरीके से लेना चाहिए। अधिकारियों को भी इन रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जो सदस्य संसदीय समितियों का हिस्सा हैं, उनके पास सार्वजनिक सेवा का अच्छा-खासा अनुभव होता है, जिसे वे इस तरह के विचार-विमर्श के दौरान साझा करते हैं।

बिरला के अनुसार , हमारे संस्थापकों ने लोकतंत्र की कल्पना लोगों की नब्ज और सरकार से उनकी अपेक्षाओं को समझने की एक कवायद के रूप में की थी। उन्होंने कहा कि लोगों के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें कि इन उम्मीदों और आकांक्षाओं को आवाज मिले तथा उन्हें पूरा किया जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया , शासन में अधिक पारदर्शिता से सरकारों का कामकाज बेहतर होगा।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से एमएसपी पर दालों की खरीद करेगी केंद्र सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के अपने प्रयासों के तहत मध्य प्रदेश से मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश से उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करेगी। मंगलवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद को मंजूरी दी।

इस योजना के तहत खरीद तब की जाती है, जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चले जाते हैं।

चौहान ने कृषि मंत्रियों के साथ खरीद लॉजिस्टिक्स पर भी चर्चा की और नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और राज्य के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। नेफेड और एनसीसीएफ केंद्र सरकार की ओर से फसलों की खरीद करते हैं।

बैठक के दौरान चौहान ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को अपेक्षित लाभ मिले।

चौहान ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। किसानों से सीधी खरीद से बिचौलियों का प्रभाव कम होगा और किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने किसानों के उचित पंजीकरण के लिए नवीनतम और सबसे प्रभावी तकनीकों के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की सलाह दी।

भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतों पर चिंता जताते हुए चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से इस मुद्दे के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों के सर्वोत्तम हित में हरसंभव प्रयास करेगी।

बैठक में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव

न्यायमूर्ति वर्मा के घर से बेहिसाब नकदी बरामद होने पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई : संसदीय समिति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मंगलवार को संसदीय समिति की बैठक में कई सांसदों ने पूछा कि यहां एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से बेहिसाब नकदी बरामद होने के मामले में कोई प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई? समिति ने न्याय विभाग से इस मामले पर एक विस्तृत नोट भी तैयार करने को कहा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सांसदों ने न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता की भी मांग की तथा कहा कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद पांच वर्ष की अवधि तक कोई सरकारी कार्यभार नहीं लेना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय से कई प्रश्न पूछे कि न्यायपालिका से संबंधित उठाए गए मामलों में वह क्या कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग के सचिव, जिन्होंने उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता और न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालने के मुद्दों से संबंधित 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार' पर प्रस्तुति दी थी, को उठाए गए मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और समिति की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने न्यायाधीशों की नैतिकता और आचार संहिता पर विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने वाले एक व्यापक विधेयक की भी मांग की, जो बैठक के दौरान उनके द्वारा उठाए गए थे। सांसदों ने जानना चाहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से बेहिसाब नकदी की बरामदगी के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और मांग की कि एक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। कुछ सांसदों ने यह भी पूछा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? सूत्रों ने कहा कि कुछ लोगों ने मांग की है कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के एक छोटे से मामले पर अपनी नौकरी खो सकता है, लेकिन बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद भी न्यायपालिका के एक वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कई दलों के सांसदों ने यह भी मांग की कि सरकार को अब तक संबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए था, खासकर तब जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की समिति ने नकदी की बरामदगी की बात को सही पाया है। नकदी बरामद होने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को उनकी मूल अदालत - इलाहाबाद उच्च न्यायालय - में वापस भेज दिया। उन्होंने उनके खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है।

ईपीएफओ सदस्य जल्द ही एटीएम, यूपीआई के जरिये सीधे ईपीएफ का पैसा निकाल सकेंगे

नई दिल्ली/भाषा। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ के सदस्य जल्द ही एटीएम या यूपीआई जैसे अन्य तरीकों से अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खातों को ईपीएफ से जोड़ना होगा। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें ईपीएफ का एक निश्चित हिस्सा रोक लिया जाएगा और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई या एटीएम डेबिट कार्ड जैसे विभिन्न तरीकों से निकाला जा सकेगा। सूत्र ने यह भी कहा कि इस प्रणाली को लागू करने में कुछ सॉफ्टवेयर चुनौतियां हैं, जिन्हें हल किया जा रहा है। इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को अपने ईपीएफ निकासी दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। स्वत: निपटान माध्यम के तहत आवेदन पत्र दाखिल करने के तीन दिन के भीतर निकासी दावों का बिना किसी मानव हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटारा किया जाता है। मंगलवार को इस स्वत: निपटान माध्यम की सीमा मौजूदा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है।

2025-26 में मध्यम, भारी वाणिज्यिक वाहन उद्योग के एक अंक में बढ़ने का अनुमान : अशोक लेलैंड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन खंड में चालू वित्तवर्ष में एकल अंक में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वित्तवर्ष 2024-25 में हुई तीन प्रतिशत की गिरावट से उबर रहा है।

अशोक लेलैंड लिमिटेड के अध्यक्ष (एम एंड एचसीवी) संजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चेन्नई स्थित कंपनी इस साल वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) के सबसे बड़े बाजार उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने उद्योग के परिदृश्य के बारे में पूछे जाने पर कहा , जब आप पिछले साल को देखते हैं, तो बिक्री की मात्रा में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है। हमारी समझ से यह गिरावट का लगातार चौथा साल है। उन्होंने कहा , यदि आप वाणिज्यिक वाहन

(सीवी) उद्योग को देखते हैं, तो आम तौर पर यह तीन साल तक अच्छा रहता है, और फिर यह... गिरावट के दौर से गुजरता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि उद्योग कम से कम एक अंक में बढ़ेगा। कुमार ने कहा कि उद्योग की वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश और कोर उद्योगों के अच्छे प्रदर्शन जैसे अनुकूल परिस्थितियों से प्रेरित होने की उम्मीद है। कंपनी की वृद्धि की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) कुल उद्योग वृद्धि से आगे निकलने की कोशिश करता है, और ''अशोक लेलैंड के लिए भी यह बात सच है और हम अपना बाजार हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं।

हिमाचल सरकार 700 होम गार्ड की भर्ती करेगी

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 10 साल के अंतराल के बाद 700 होम गार्ड की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि इन पदों को भरने का निर्णय 31 मई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। इस कदम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन होने की उम्मीद है।

पिछले कई वर्षों से होम गार्ड की कोई भर्ती नहीं की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इतने लंबे से भर्ती नहीं होने के कारण कर्मचारियों की काफी कमी हो गई, जिससे विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की तैनाती की मांग पूरी करने में बाधा आ रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग 8000 होमगार्ड हैं। पुलिस और नागरिक प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन, चुनाव ड्यूटी और त्योहारों व सार्वजनिक समारोहों के दौरान भीड़ प्रबंधन में होम गार्ड सहायता करते हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और वन अग्नि के दौरान सबसे पहले सहायता करने के लिए सामने आते हैं।

दो कंपनियों का वर्चस्व अच्छी बात नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए: सिंधिया

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि किसी भी क्षेत्र में दो कंपनियों का वर्चस्व अच्छी बात नहीं है और हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। 'ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम' के एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और सरकार 15 अगस्त से पहले छह गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त करने के नियम जारी करेगी। इसका इस्तेमाल वाई-फाई सेवाओं और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए किया जाएगा।

सिंधिया ने कहा , हमारा काम यथासंभव अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है और प्रत्येक क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा संभव कराना है। एक या दो कंपनियों का वर्चस्व पर्याप्त नहीं है। इससे पहले, कार्यक्रम में दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में भी द्वैधाधिकार है और केवल दो सक्रिय सेवा प्रदाता हैं तथा उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराने के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है।

राज्य का दर्जा बहाल होने पर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने को तैयार: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर/भाषा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने के बाद विधानसभा को भंग करके नए सिरे से चुनाव कराया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

यहां से 52 किलोमीटर दूर गुलमर्ग में अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा , मैंने अखबार में पढ़ा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव फिर से कराने होंगे। उन्हें ऐसा करने दीजिए, किसने रोका है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा , मुझे पता है कि यह खबर कहां से आई है। मुझे पता है कि यहां अखबार में यह खबर किसने प्रकाशित कराई...यह सिर्फ विधायकों को डराने के लिए प्रकाशित की गई। राज्य का दर्जा किसी विधायक या सरकार के लिए नहीं है। यह राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए है और हम विधायक इसमें बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा भंग करने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसा करें।

अब्दुल्ला ने कहा , जिस दिन राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा, उसके अगले दिन हम राज्यपाल के पास जाएंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। हमें डराने की कोशिश न करें...राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है और इसे हमें वापस दें। अखबारों में खबरें छपवाना बंद करें, यह काम नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार डेढ़ वर्ष में सभी मोर्चों पर विफल रही है : पायलट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि पिछले डेढ़ साल में यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है।

कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सात जुलाई को रायपुर में किसान-जवान-संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी औद्योगीकरण और निवेश में विश्वास करती है, लेकिन भाजपा की मंशा सिर्फ चुनिंदा लोगों को खदान और खनिज देने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस नेता पायलट ने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में संचालित 17 कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा ने बंद कर दिया, जिससे कांग्रेस को इसका

श्रेय न मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ डेढ़ साल में 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए (बलौदाबाजार में), जबकि हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में लोग मर रहे हैं, यहां महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। पायलट ने कहा , कांग्रेस हमेशा निवेश और उद्योग के पक्ष में रही है। सरकारी क्षेत्र के अलावा, निजी क्षेत्र में संसाधन होने चाहिए तथा शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

मुंबई में नाले से बरामद अंडों से 22 अजगर निकले

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले महीने एक नाले से बरामद किए गए अंडों से 22 अजगर निकले हैं, जो भारतीय राक पाइथन प्रजाति के हैं। राज्य के वन विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र वन विभाग और वन्यजीव कल्याण के लिए गैर सरकरी संगठन 'रेसक्विंक एसोसिएशन' के संयुक्त प्रयासों से 22 अजगरों को नियंत्रित वातावरण में इनक्यूबेटर में रखा गया और इन अंडों को सेया गया। 'रेसक्विंक एसोसिएशन' के संस्थापक और अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि मई में मानसून से पहले रखरखाव कार्य के दौरान ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग पर एक नाले से नौ फुट लंबी मादा अजगर के साथ ये अंडे बरामद किए गए थे। 'रेसक्विंक एसोसिएशन' के प्राणी वैज्ञानिक चिन्मय जोशी ने बताया कि बचाए गए अजगर को स्वस्थ घोषित कर जंगल में छोड़ दिया गया जबकि अंडों को 'आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन' के लिए संगठन को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह से ही अंडों में अजगर के छोटे-छोटे बच्चों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। शर्मा ने बताया कि उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2028 में राज्य में फिर से कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को विश्वास जताया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी 2028 में एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता तक पहुंचें और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत करें।

यहां राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, महिला आरक्षण और विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने सहित आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (तेदपा) और कांग्रेस क्रमशः 1994-2004 और 2004 से 2014 तक दो-दो बार सत्ता में रहीं। इसी तरह, तेलंगाना के गठन के बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 2014 से 2023 तक दो बार सत्ता में रही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, महिला आरक्षण और विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव एक साथ कराने से पार्टी नेताओं के लिए अधिक राजनीतिक अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्य हवाई अड्डों पर निगरानी के दौरान

डीजीसीए ने प्रविमानन पारिस्थितिकी तंत्र में कई खामियां पाईं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को कहा कि प्रमुख हवाई अड्डों पर की गई निगरानी में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में कई खामियां सामने आई हैं। नियामक ने कहा कि इनमें कई ऐसे मामले शामिल हैं, जहां विमान में खामियां फिर से दिखाई दीं और रनवे पर केंद्र रेखा का निशान धुंधला हो गया था।

अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पृष्ठभूमि में की गई इस जांच में उड़ान संचालन, उड़ान योग्यता, रैंप सुरक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण, संचार, नेविगेशन प्रणाली और उड़ान-पूर्व चिकित्सा मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने बयान में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में एयरलाइन कंपनियों या किसी अन्य इकाई का नाम बताए बिना कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित पक्षों को सात दिन के भीतर निष्कर्षों के बारे में बता दिया गया। बयान में कहा गया कि निगरानी के दौरान, एक अनुसूचित एयरलाइन की घरेलू उड़ान घिसे हुए टायरों के कारण रुकी हुई पाई गई और आवश्यक सुधार के बाद ही उसे छोड़ा गया। नियामक ने कहा कि ऐसे कई मामले थे, जिनमें पहले पता चल चुकी खामियां विमान में फिर से दिखाई दीं, जिससे अप्रभावी निगरानी और अपर्याप्त सुधार का संकेत मिलता है। नियामक ने यह भी पाया कि एक सिम्युलेटर विमान की बनावट से मेल नहीं खा रहा था और सॉफ्टवेयर भी वर्तमान संस्करण में 'अपडेट' नहीं किया गया था। संयुक्त महानिदेशक के नेतृत्व में दो दलों ने दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर रात और सुबह के समय निगरानी की।

'बिजली क्षेत्र को 2032 तक 42 लाख करोड़ रु. के निवेश की जरूरत : मनोहर लाल'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से दक्षता में सुधार करने को कहा है, क्योंकि वितरण बिजली क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को 2032 तक कुल 42 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी।

पटना में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

मंत्री ने राज्यों को राज्य में एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने पर विचार करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वितरण बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और बिजली क्षेत्र को वर्ष 2032 तक अनुमानित 42 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है।

मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरकारी विभागों के बकाया को समय पर जारी करने का एक तरीका है।

आम बजट 2025-26 में, पारेषण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों के पूंजीगत व्यय का समर्थन करने को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण में 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि राज्यों को बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा की बढ़ी हुई हिस्सेदारी की ओर बढ़ रहा है और यह वर्ष 2014 में 32 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल, 2025 में 49 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर भी प्रकाश डाला।

सिद्दरामय्या ने राष्ट्रपति से किया कर्नाटक के सात प्रमुख विधेयकों को मंजूरी देने का अनुरोध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सात प्रमुख विधेयकों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। जिन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है उनमें शिक्षा, खनन कराधान, सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार जैसे विधेयक शामिल हैं।

राष्ट्रपति से भेंट करने के बाद सिद्दरामय्या ने संवाददाताओं से कहा, ''सात विधेयक अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। मैंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।''

राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख विधेयकों में बाल निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (कर्नाटक संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य में मौजूदा आरटीई ढांचे में सुधार करना है। कर्नाटक कर विधेयक 2024 का उद्देश्य राज्य के खनिज संसाधनों से राजस्व बढ़ाना है, जबकि कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (संशोधन) अधिनियम 2025 सरकारी खरीद में अधिक जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। इन विधेयकों में पंजीकरण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक 2024 और इसके समकक्ष विधेयक 2025 के साथ-साथ नोटरी (कर्नाटक संशोधन) विधेयक 2025 भी शामिल हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित हैं। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक भी उन विधेयकों की सूची में शामिल है, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है, क्योंकि वे ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिनके तहत राज्य में कार्यान्वयन से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

'आपातकाल' वह समय था जब सत्ता के लिए संविधान की बलि दी गई थी : येडीयुरप्पा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस सिद्दरामय्या ने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह सिर्फ उनकी सत्ता के लिए हमारे पवित्र संविधान की बलि दी गई। सिटीजन फॉर सोशल जस्टिस बेंगलूरु ने आज टाउन हॉल में ''1975 आपातकाल का 50वां साल-काले दिन' शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और जनता के अधिकारों को अपनी तानाशाही सत्ता के लिए स्वतंत्रता की आवाजों का गला घोंटकर छीन लिया गया था।

उन्होंने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों का हिटलरी कुशासन आज भी गुस्से की आग को भड़काता है। आपातकाल लगाने के पीछे एकमात्र कारण न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका व्यवस्था को अपने कब्जे में रखकर सत्ता में बने रहना था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। लोकतंत्र का गला घोंटा गया और अराजकता पैदा की गई। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी मिलने के बाद सत्ता के लिए ऐसा किया। अगर यह सच नहीं होता तो डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अपने द्वारा दिए गए महान संविधान की आकांक्षाओं का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोपने की गलती नहीं करते।मुख्य वक्ता के रूप में स्तंभकार और आर्थिक विचारक एस. गुरुमूर्ति ने कहा कि 2024 में जीतने के बाद राहुल गांधी संविधान की नुमाइश करने लगे हैं और कहा कि वे संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी दादी ने आपातकाल के दौरान इसी संविधान की अनदेखी की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी को संविधान, संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में बात करने का नैतिक और कानूनी अधिकार है। 25 जून को संविधान की हत्या का दिन माना जाता है। यह 18 महीने का सदमा नहीं था; उन्होंने बताया कि संविधान में संशोधन करके एक ही परिवार की तानाशाही को अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण जैसे आम लोगों ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नव निर्वाचित गैर कांग्रेसी राजनीतिक नेता आपातकाल के लिए जिम्मेदार कांग्रेस नेताओं को दंडित करेंगे, यह उम्मीद टूट गई।कांग्रेस फिर सत्ता में आई। अगले 34 वर्षों में आपातकाल के लिए जिम्मेदार लोगों ने 28 वर्षों तक देश पर शासन किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों और संस्थाओं की कड़वी यादों को मिटाने में सक्षम हैं। बाद में राजीव गांधी 415 सांसदों के साथ सत्ता में आए। भाजपा के पास केवल दो सांसद थे। भाजपा मर चुकी है और उसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। लेकिन, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि केवल दो ही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वे फिर से आपातकाल लगाने के लिए तैयार हैं। इस संगोष्ठी में भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस सिद्दरामय्या, एस गुरुमूर्ति, सेवानिवृत्त कुलपति विष्णुकांत चट्टापल्ली, केंद्रीय ललित कला अकादमी और राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और कलाकार सीएस कृष्णा शेट्टी ने भाग लिया। पद्मिनी श्रीधर ने देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम' गाया। यह आपातकाल के 21 महीनों के काले दौर को याद करने का दिन था। आपातकाल की शैतानी घटनाओं को याद किया गया। संघर्ष में आरएसएस के स्वयंसेवकों और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। आपातकाल के काले दिन की निंदा की गई।

दुर्लभ खनिज के उत्पादन के लिए सब्सिडी योजना पर निर्णय 15-20 दिन में होगा : कुमारस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा है दुर्लभ खनिज (पृथ्वी चुंबक) के घरेलू उत्पादन पर सब्सिडी योजना शुरू करने के बारे में 15 से 20 दिन में निर्णय लिया जाएगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी है। भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव कामरान रिजवी ने कहा कि यदि कुल प्रोत्साहन 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होता है, तो योजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।

कुमारस्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हैदराबाद की एक कंपनी है... वह इसमें रुचि दिखा रही है। उन्होंने वादा किया है कि वे इस साल के अंत यानी दिसंबर तक 500 टन की आपूर्ति करेंगे। हमने खान मंत्री के साथ चर्चा की है। हमारे सचिव और हमारा मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं, अंततः, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा।''

चीन द्वारा प्रमुख धातुओं के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत सहित कई देशों में वाहन और सेमीकंडक्टर चिप के विनिर्माण में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ है। सचिव ने कहा कि दुर्लभ खनिज के वास्तविक उत्पादन में करीब दो वर्ष लगेंगे। इस दौरान सरकार, उद्योग के साथ मिलकर जापान और वियतनाम सहित अन्य वैकल्पिक स्रोतों से खरीद की संभावना तलाशेगी।

रिजवी ने कहा, ''आप जानते हैं कि जापान और वियतनाम में दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं। हम वहां से इसे लेने का प्रयास कर रहे हैं।''

दुर्लभ पृथ्वी चुंबक में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (एनडीएफईबी) शामिल है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन (दोपहिया व यात्री वाहनों) में ट्रैक्शन मोटर और इलेक्ट्रिक वाहन एवं परंपरागत वाहन (आंतरिक दहन इंजन) में पावर स्टीयरिंग मोटर (यात्री वाहनों में) के लिए किया जाता है। सब्सिडी से दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड को चुंबक में बदलने के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने को निवेश मिल सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ मैग्नेट्स लिमिटेड के पास ही दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का भंडार है। कंपनी के पास पास 1,500 टन चुंबक बनाने के लिए पर्याप्त दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं।

रिजवी ने कहा कि योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए जाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोत्साहन की मात्रा कितनी होगी। उन्होंने कहा, यह प्रोत्साहन के स्तर पर निर्भर करता है। यदि यह 1,000 करोड़ रुपये से कम है, तो (भारी उद्योग) मंत्री और वित्त मंत्री इसे कर सकते हैं। यदि यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इसे मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक आवश्यक सब्सिडी की मात्रा का पता नहीं है। हितधारकों के साथ बातचीत जारी है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं.. कोई 50 प्रतिशत चाहता है, कोई 20 प्रतिशत चाहता है, इसलिए यह प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन होगा, तब ही हमें आवश्यक समर्थन की मात्रा का पता चलेगा।''

'भारत में एक वक्त में पसंद किया जाता था गहरी त्वचा को'

बेंगलूरु। भारत के दक्षिणी इलकों में एक दौर था जब क्षेत्र के लोग गहरे रंग की त्वचा पसंद करते थे? वास्तव में, वे अपनी त्वचा को गहरा करने के लिए कुछ न कुछ लगाते थे। बेंगलूरु में इटली के महावाणिज्यदूत अल्फोंसो टैगलियाफेरी ने बताया कि इस बात का पता फिल्म 'द इंडिया दे सॉ' के लिए शोध करते समय लगा। अल्फोंसो ने बताया कि 30 मिनट की यह फिल्म 13वीं और 14वीं सदी के दौरान वेनिस के दो महान यात्रियों मार्को पोलो और निकोलो डे कोंटी की यात्राओं का वर्णन करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म भारत और इटली के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

फिल्म के निर्देशक गणेश शंकर राज के अनुसार, फिल्म में जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी हैं, जैसे कि उन दिनों लोग अपनी त्वचा को काला दिखाने के लिए कोई तेल लगाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि वह तिल का तेल होता है और विजयनगर साम्राज्य में भी होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। फिल्म को कन्नड़ भाषा में भी डब किया गया है और जल्द ही इसे तमिल में भी डब किया जाएगा।

ईडी ने ऐश्वर्या गौड़ा से संबंधित धोखाधड़ी मामले में 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

बेंगलूरु/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेताओं से निकटता का हवाला देकर कई लोगों को धमकाने और ठगी करने के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी ऐश्वर्या गौड़ा सहित 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अभियोजन शिकायत 21 जून को बेंगलूरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई। इस मामले में हाल में 3.98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।

एजेंसी के मुताबिक, मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस नेता डी के सुरेश से भी बेंगलूरु स्थित कार्यालय में सोमवार को पूछताछ की गई थी। ईडी ने 33 वर्षीय गौड़ा को अप्रैल में उनके, कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और कुछ अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। कुलकर्णी ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया था।

ईडी ने गौड़ा, उनके पति हरीश के एन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि गौड़ा, उनके पति और अन्य लोगों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश' रची, जिसके तहत उन्होंने कई लोगों को ठगा और धोखा दिया। उन्होंने अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से सोना, नकद और बैंक खातों के माध्यम से धन प्राप्त किया। गौड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व सांसद डी के सुरेश के नाम का इस्तेमाल किया और खुद को उनकी बहन बताया।

सिद्दरामय्या ने सीतारमण से मुलाकात की, 16वें वित्त आयोग से वृद्धि समर्थक कर हस्तांतरण की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच कर से प्राप्त राशि के हस्तांतरण में वृद्धि समर्थक नजरिया अपनाने के लिए केंद्र से समर्थन मांगा। सिद्दरामय्या ने बैठक के दौरान सीतारमण को 15वें वित्त आयोग के तहत कर्नाटक को हुए महत्वपूर्ण घाटे के बारे में जानकारी दी और एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले 16वें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर पूल से राज्य के लिए अधिक आवंटन की मांग की।बैठक के बाद सिद्दरामय्या ने संवाददाताओं से कहा, ''मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा कर मिली राशि के हस्तांतरण में राज्य के हिस्से में कटौती के कारण कर्नाटक को कुल मिलाकर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।''

मुख्यमंत्री ने एक अतिरिक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया और राज्यों को केंद्र से राजकोषीय हस्तांतरण में लगातार असंतुलन को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत कर हस्तांतरण में राज्य का हिस्सा 4.713 प्रतिशत से घटकर 3.647 प्रतिशत रह गया है। कर्नाटक को विशेष अनुदान में 11,495 करोड़ रुपये से भी वंचित कर दिया गया, जिसके चलते कुल 80,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर 2.5 लाख टन आम खरीदेगा केंद्र

बेंगलूरु/नईदिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को घोषणा की कि वह कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन आम खरीदेगा।

यह खरीद, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से की जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपने गृह राज्य में आम उत्पादकों के बारे में चिंता जताए जाने के बाद लिया गया। चौहान ने कुमारस्वामी को लिखे पत्र में कहा, ''मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कर्नाटक राज्य में विपणन वर्ष 2025-26 के लिए आम पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2,50,000 टन की अधिकतम मात्रा को मंजूरी दी गई है।'' कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कदम से राज्य के आम उत्पादकों को राहत मिलेगी, जहां कीमतें तेजी से गिरकर 400 रुपये प्रति क्विंटल रह गई हैं - जो खरीद मूल्य से चार गुना अधिक का अंतर है।

लोकायुक्त अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आठ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे

बेंगलूरु। लोकायुक्त के अधिकारियों ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मंगलवार को आठ सरकारी अधिकारियों से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। लोकायुक्त के अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों के घरों, कार्यालयों और अन्य स्थानों पर छापे मारे। लोकायुक्त के अनुसार ये छापे जिन लोगों से जुड़े ठिकानों पर मारे गए, उनमें बेंगलूरु के गोविंदराज नगर में बीबीएमपी सहायक अभियंता प्रकाश; जैविक खेती, शिवमोगा के एसोसिएट रिसर्च डायरेक्टर डॉ. एस प्रदीप, टाउन नगर पालिका, चिक्कमगलुरु में लेखा अधिकारी लता मणि; बेंगलूरु के अनेकल में टाउन नगर पालिका में मुख्य अधिकारी केजी अमरनाथ; गदग के टाउन पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुवराज; मलाप्रभा परियोजना, धारवाड़ में इजीनियर अशोक वसानद और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, कालबुरगी में कार्यकारी अभियंता मल्लिकार्जुन अलीपुर शामिल हैं।

मंत्री ने आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के आवास मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत मकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया और मामले की गहन जांच की मांग की। मंत्री, अलंद से सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक बी आर पाटिल के दावों का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मकान के बदले गरीब परिवारों से रिश्वत ली जा रही है।

खान ने संवाददाताओं से कहा, क्या ऐसा कोई मामला है, जहां मकान आवंटित करने के लिए पैसे लिए जा रहे हों? बी आर पाटिल मुझे बताएं कि किसने पैसे मांगे। हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने रिश्वत ली - उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पाटिल से आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को पत्र लिखकर कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच की मांग करें। अपना रुख स्पष्ट करते हुए खान ने कहा कि उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा, मंत्री के तौर पर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जांच करें कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है। अब तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के आरोपों का खंडन करते हुए खान ने कहा, मैं इतनी गरीबी में नहीं हूं कि मुझे गरीबों से पैसे लेने की जरूरत पड़े। अगर मैंने मकान आवंटित करने के लिए पैसे लिए हैं, तो मुझे बददुआएं दी जानी चाहिए। क्या गरीबों का शोषण करके मेरे परिवार या मुझे कुछ हासिल होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार केवल पंचायतों को है, विधायकों को नहीं। इस विवाद ने विपक्षी भाजपा और जद (एस) को मौका दे दिया, जिन्होंने खान के इस्तीफे और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

प्रज्ज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए फिर उच्च न्यायालय का रुख किया

बेंगलूरु। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना ने मंगलवार को एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में जमानत देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने पहले आरोपों की गंभीरता और गवाहों से छेड़छाड़ के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

नवीनतम याचिका पर सुनवाई के दौरान रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने कहा कि पिछले आदेश के बाद से परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ अदालत के समक्ष कार्यवाही में लंबे समय तक देरी रेवन्ना की जमानत याचिका पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त कारण है। नवदगी ने यह भी बताया कि कथित घटना के चार साल बाद शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता ने शुरुआत में रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उसके बयान दर्ज करने के दौरान ये विशिष्ट आरोप लगाए गए थे।

भाजपा के पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े और तीन अन्य पर मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े, उनके सुरक्षाकर्मी, चालक और एक अज्ञात व्यक्ति पर एक परिवार की कार रोककर उन पर हमला करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना कथित तौर पर सोमवार शाम को घटी। बेंगलूरु के हेलेनाहल्ली निवासी सैफ खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, एक कार में जा रहे हेगड़े समेत चार लोगों ने तुमकुरु-बेंगलूरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुत्तारिया कॉलेज के पास कथित तौर पर उनके वाहन को रोका और उन पर हमला कर दिया।

खान ने कहा कि वह और उनका परिवार तुमकुरु में एक शादी से कार में लौट रहे थे, जब उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने कथित तौर पर अधिकारी होने का दावा किया, फिर खान, उनके भाई सलमान खान, उनकी मां गुलमीर उन्नीसा और एक अन्य परिजन इलियास खान पर हमला कर दिया।

संबोधन

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मंगलवार को बेंगलूरु में भाजपा कार्यालय में राज्य भाजपा नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

मेरे बयान को गलत समझा गया, राज्य के पास बजट की कोई कमी नहीं : डॉ. परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास किसी भी मद में धन व बजट की कोई कमी नहीं है तथा उनके पूर्व में दिए गए बयान को गलत समझा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बागलकोट जिले के बादामी में एक सभा को संबोधित करते समय सोमवार को दिए गए बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के पास धन नहीं है, को लेकर सफाई दी।

उनकी टिप्पणी ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी तथा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी सरकार पर निशाना साधने के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। परमेश्वर ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से कहा, ''मैंने ऐसा नहीं कहा, किसने कहा कि धन नहीं है? मैंने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि हमने रिकॉर्ड बजट पेश किया है....जैसे किसी ने भाषण के दौरान मजाक में कुछ कहा मैंने भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी, बस इतना ही।''

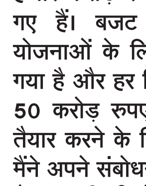

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या द्वारा 4.09 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा, ''मैंने कहा है कि धन की कोई कमी नहीं है। बजट में सिंचाई के लिए 22 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में पांच गारंटी योजनाओं के लिए आवंटन किया गया है और हर विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने अपने संबोधन में यह सब कहा है। जब किसी ने मजाक में कुछ कहा, तो मेरी प्रतिक्रिया भी शायद वैसी ही रही।'' उन्होंने कहा, ''मैं अब आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि हमारी सरकार के समक्ष कोई वित्तीय संकट नहीं है। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। कभी-कभी, धन जारी करने में देरी हो सकती है, क्योंकि धन जारी करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और आकलन तैयार करने जैसी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारी सरकार के पास किसी भी कारण से धन की कोई कमी नहीं है। अगर किसी ने मेरे बयान को गलत समझा है, तो मैं इसे सही कर रहा हूं।''

गृह मंत्री ने सोमवार को बादामी में एक सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक भीमसेन बी. चिम्मानकट्टी को ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले बादामी शहर के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये की परियोजना तैयार करने और इसे केंद्र को भेजने का सुझाव दिया था, क्योंकि राज्य के पास धन नहीं है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा को युक्तिसंगत बनाने की योजना को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवास (सीटीएच) की सीमा को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव मण्डल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव को अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस प्रस्ताव में मानवीय गतिविधियों वाले कुछ पहाड़ी इलाकों को अलग करते हुए सीटीएच की सीमाओं को संशोधित करना और होने वाले नुकसान की भरपाई 'बफर जोन' से करना शामिल है। इस प्रस्ताव से इस साल की शुरुआत में उच्च्तम न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दी गईं, कई संगमरमर और डोलोमाइट खदानों को फायदा होने की संभावना है।

राजस्थान के वन अधिकारी अरिजीत बनर्जी ने कहा, सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच की सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव सोमवार को वन्यजीव मंडल की बैठक में रखा गया और इसे पारित कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने उन खदानों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की जिन्हें सीमा के युक्तिकरण से लाभ होगा। ये खदानें खोह, पालपुर, तिलवाड़, गोरधनपुरा, मल्लाना, डूंडपुरी, जयसिंहपुरा और कलवार गांवों में और उसके आसपास हैं। प्रस्ताव के अनुसार सीटीएच से बाहर रखे गए इलाकों – मुख्य रूप से मानवीय गतिविधि से प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र – को बाघ अभयारण्य के बफर जोन में जोड़ा जाएगा। ये क्षेत्र अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बदलाव से स्थानीय समुदाय और बाघ अभयारण्य प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय ने बाघ अभयारण्य के अंदर पैदल और निजी वाहनों से लोगों के बेरोक-टोक प्रवेश के मुद्दों के बारे में स्वत: संज्ञान लिया था। 2024 में न्यायालय ने केंद्रीय अधिकारसंपन्न समिति (सीईसी) को इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जुलाई 2024 में सीईसी की रिपोर्ट के बाद, राजस्थान सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय ने राज्य को एक साल के भीतर युक्तिकरण कार्रवाई पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य मंडल में पारित प्रस्ताव अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) के समक्ष रखा जाएगा, जिसकी बैठक 26 जून को देहरादून में होने वाली है।

हालांकि वन विभाग के कुछ अधिकारी सीमा के युक्तिकरण का विरोध भी कर रहे हैं। इन्होंने नाम उजागर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि परिधीय पहाड़ियों को बाहर करने से बाघ अभयारण्य का भीतरी संपर्क एक तरह से टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की पहाड़ियां अनावश्यक नहीं बल्कि बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान ने 2007-08 में सरिस्का के लिए सीटीएच की सीमा निर्धारित की थी, लेकिन जमीन संबंधी कई विवादों के कारण अधिसूचना लंबित रही। फिलहाल राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोनों अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके चलते विवादास्पद मुद्दों को निपटाने पहल की गई है।

राजस्थान में अनेक जगह भारी बारिश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते बारिश का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में अनेक जगह भारी से अति भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में मानसून की सक्रियता अभी बनी रहेगी। इसके अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते चौबीस घंटे में विशेषकर पूर्वी राजस्थान में कई जगह भारी से अतिभारी बारिश हुई। सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश बारां के मांगरोल में दर्ज की गई। इसी तरह बारां में किशनगंज में लगभग 110 ममी. और शाहाबाद में 170 ममी. बारिश हुई। वहीं सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, अलवर व झुंझुनू जिले में कहीं कहीं 30 से 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई।

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भी कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी या अतिभारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25-27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में एक नया मौसमी तंत्र बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून से फिर भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।

शासन सचिव ने भविष्य की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को मुख्यालय के सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग के कार्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर भविष्य की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, शहरों की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं आदि का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर निकायों की कार्य क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख चुनौतियों जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलभराव, स्ट्रीट वेंडर ज़ोन का सुव्यवस्थित संचालन, राजस्व वृद्धि एवं नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को विस्तार देने की दिशा में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचना ही विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जैन ने अधिकारियों को कहा कि सभी नगरीय निकाय जनसुनवाई तंत्र को और अधिक संवेदनशील एवं सुदृढ़ बनाए तथा समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता को आधार बनाकर ही सुशासन की स्थापना संभव है। बैठक में विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह, मुख्य अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उदयपुर में फ्रांसीसी पर्यटक से दुष्कर्म का मामला, आरोपी फरार

जयपुर। उदयपुर शहर में फ्रांस की एक पर्यटक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी फरार है। आरोप है कि व्यक्ति इस पर्यटक को एक पार्टी से बहला-फुसलाकर अपने किराए के अपार्टमेंट में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अनुसार घटना सोमवार को बड़गांव थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि 22 जून को दिल्ली से उदयपुर पहुंची महिला अंबामाता क्षेत्र के एक होटल में ठहरी थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गई है और उसके बयान के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताय कि आरोपी फरार है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पीड़िता आरोपी के संपर्क में कैसे आई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महिला टाइगर हिल स्थित 'द ग्रीक फार्म कैफे एंड रेस्ट्रो' में एक पार्टी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी सिद्धार्थ से हुई। उन्होंने बताया, आरोपी ने महिला को आसपास की जगहें दिखाने के बहाने बाहर बुलाया और बाद में उसे सुखेर में अपने किराये के अपार्टमेंट में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने बार-बार होटल लौटने की मिन्नत की लेकिन लेकिन आरोपी ने मना कर दिया।

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का निकला सफल परिणाम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले झालावाड़ और बारां जिलों के 27 ग्रामों के शेष मकानों के लिए 36.97 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल से वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। अब शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि उपलब्ध हो सकेगी।

परियोजना के तहत पहले से ही झालावाड़ और बारां के 47 ग्रामों की डूब प्रभावित भूमि और 29 ग्रामों के आंशिक व पूर्ण डूब प्रभावित मकानों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि, इस दौरान राजकीय भूमि (चारागाह, सिवायचक, वन भूमि) पर बने मकानों को मुआवजे के लिए शामिल नहीं किया था। इनमें झालावाड़ की तहसील खानपुर और अकलेरा के 17 तथा बारां की तहसील छीपाबड़ौद के 10 गांव शामिल हैं। अब इनके 1090 मकानों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने 22 और 23 अप्रैल, 2025 को परवन बांध निरीक्षण के दौरान प्रभावितों से मुलाकात कर समस्या को गंभीरता से सुना। इसके बाद रावत ने विभागीय अधिकारियों को राजकीय भूमि पर स्थित मकानों/परिसम्पत्तियों के लिए विशेष राशि के रूप में मुआवजे का प्रस्ताव तैयार राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे।

रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का ही परिणाम रहा कि वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त हुई है। मुआवजा राशि मिलने से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही, परवन परियोजना के शेष निर्माण कार्यों में भी गति आएगी। उल्लेखनीय है कि परियोजना में 571 ग्रामों की 2.0 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। साथ ही, 1402 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 'हाड़ौती के लिए महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षी परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावितों को न्याय और सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा। इससे परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी और निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगा।

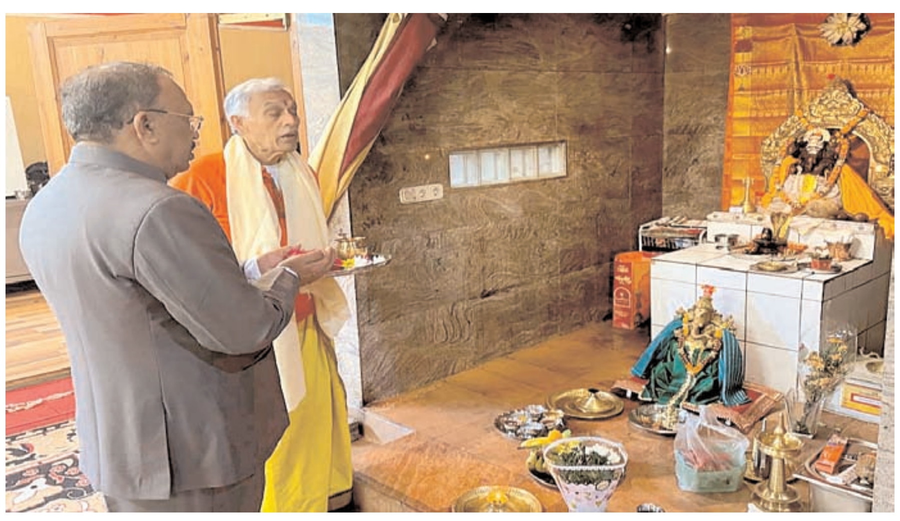

देवनानी ने बर्लिन में निर्माणाधीन गणेश मंदिर का किया दौरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में निर्माणाधीन गणेश मंदिर का अवलोकन किया। देवनानी ने इस मंदिर के निर्माण पर प्रसन्नता जाहिर की। उल्लेखनीय है कि देवनानी वर्तमान में जर्मनी प्रवास पर हैं। देवनानी ने मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशी की कामना की। देवनानी ने मंदिर परिसर का अवलोकन कर यहां स्थापित होने वाली मूर्तियां और अन्य निर्माण की जानकारी ली। देवनानी ने मंदिर के ट्रस्टी विल्वनाथन कृष्णामूर्ति से मंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की। देवनानी को कृष्णामूर्ति ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। बर्लिन में सनातन परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यह मंदिर पूजा, विवाह समारोह, गृह प्रवेश और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए स्थान भी उपलब्ध कराएगा। देवनानी को बताया कि यह मंदिर जर्मनी का सबसे बड़ा मंदिर होने का गौरव रखता है। मंदिर का निर्माण सनातन, आध्यात्मिक, पारंपरिक, वैदिक और आगम शास्त्रों के अनुसार किया गया है। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने देवनानी को बताया कि मंदिर का निर्माण विल्वनाथन कृष्णमूर्ति के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने 50 साल पहले बर्लिन में आकर मंदिर बनाने का सपना देखा था। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से जन सहयोग से किया गया है। इसमें किसी भी सरकारी सहायता का उपयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक स्थान है बल्कि यह बर्लिन में प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह ऐतिहासिक मंदिर पारंपरिक वैदिक एवं आगम शास्त्रों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक पवित्र स्थल है बल्कि यह जर्मनी में बसे भारतीय एवं विशेष रूप से तमिल मूल के लोगो के लिए एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जर्मनी प्रवास के दौरान बर्लिन में महापौर के कार्यालय एवं जर्मन स्टेट असेंबली का अवलोकन किया। बर्लिन महापौर को वहां रेजीरेंडर बर्गोमास्टर कहा जाता है। देवनानी को बर्लिन मेयर ने बताया कि बर्लिन की स्टेट असेंबली का भवन न केवल बर्लिन की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है अपितु आधुनिक लोकतंत्र की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का जीवंत उदाहरण भी है। इस अवसर पर देवनानी ने बर्लिन की कार्यकारी प्रणाली, लोकतांत्रिक स्वरूप एवं डिजिटल गवर्नेंस की बारीकियों को निकटता से देखा और उसकी पारदर्शिता व सुगठित व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने बर्लिन सीनेट के प्रशासनिक तंत्र और जनहित नीतियों के क्रियान्वयन मॉडल को संगठित लोकतंत्र की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति बताया। देवनानी ने कहा बर्लिन जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर का प्रशासनिक मॉडल यह दर्शाता है कि तकनीक, नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता के साथ एक शहर किस प्रकार भविष्य की दिशा तय कर सकता है। राजस्थान विधानसभा के लिए यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी है। इस ऐतिहासिक दौरे के माध्यम से न केवल प्रशासनिक अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं भारत और जर्मनी के मध्य लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी चेतना और संवाद की भूमि भी सशक्त हुई।

सीमाई क्षेत्र में संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर के सीमाजन कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंटकर जिले में चल रहे जासूसी नेटवर्क एवं यहां कार्यरत कंपनियों और नहरी मुरब्बों पर बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के आगमन पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

समिति के जिला मंत्री भूरसिंह बीदा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कार्यरत कंपनियों एवं नहरी मुरब्बों पर बाहरी संदिग्ध लोग बिना जांच पड़ताल के प्रवेश कर रहे हैं। कई संदेहास्पद लोग तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी शिनाख्त करके कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में जासूसी का नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों की तत्परता से हालांकि, शकूर खान सहित कुछ लोग पकड़े गये हैं, लेकिन जिले के सीमावर्ती एवं नहरी क्षेत्र में निवास कर रहे पाकपरस्त लोगों की पहचान करके उन पर कानूनी शिकंजा करने की जरूरत है। बीदा ने बताया कि समिति ने पाक विस्थापित उन परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी मांग की है।

'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों में लाएं गति : दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों में ऑडिट और आमसभा की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पन्न होनी चाहिए। आमसभा केवल औपचारिकता नहीं हो, बल्कि इसमें लोगों के सुझाव प्राप्त करने और नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर पैक्स स्तर तक खाद-बीज की गुणवत्ता की जांच करने तथा विभाग में मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

दक मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आमसभा आयोजित करने के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक की समयावधि निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में शत प्रतिशत पैक्स की आमसभा अनिवार्य रूप से सम्पन्न हो। साथ ही, पैक्स के सूचना पटल में वर्णित जमाओं व अन्य संबंधित जानकारियों के विवरण के साथ आमसभा के फोटो भी मंगवाए जाएं। इससे सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास खाद-बीज विक्रय के लाइसेंस हैं, उनका आगामी दिनों में अभियान चलाकर आवश्यक रूप से निरीक्षण करवाया जाए। निरीक्षण के दौरान खाद-बीज की गुणवत्ता की जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में और गति लाने तथा गो-लाइव हो चुकी पैक्स को हैण्ड-होल्डिंग सर्टिफिकेट यथाशीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गो-लाइव हो चुकी पैक्स की ई-ऑडिट करवाई जाए। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया कि अब तक 5,301 पैक्स गो-लाइव हो चुकी है जबकि, 2,398 पैक्स को हैण्ड होल्डिंग प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 713 पैक्स द्वारा ई-ऑडिट करवाई जा चुकी है। दक ने बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में अपेक्षित प्रगति हासिल करते हुए एनसीडी पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में पैक्स के गठन तथा निष्क्रिय सहकारी समतियों के अवसायन के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

दक ने विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे गोदामों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप इन्हें किराये पर देने की प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए। इससे पैक्स की आय में वृद्धि होगी। दक ने कहा कि पैक्स द्वारा जन औषधि केन्द्र का संचालन करने से पूर्व उसकी व्यवहार्यता परखी जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स द्वारा एफपीओ के साथ ही नये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। इससे उनकी अतिरिक्त आय हो सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

उन्होंने नये गठित होने वाले पैक्स के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता अनिवार्य किए जाने पर भी जोर दिया। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता के अनुसार भारत सरकार से डेयरी सहकारी समितियों के लक्ष्य में संशोधन का आग्रह किया जा सकता है।

अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है 'माफिया मुक्त' गाजीपुर : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गाजीपुर (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि 'माफिया मुक्त' हो चुका गाजीपुर जिला अब विकास की प्रक्रिया के साथ आधुनिक मूलभूत अवसंरचना का लाभ प्राप्त कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गाजीपुर जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण जिले का इतिहास रामायण काल और उससे भी प्राचीन है। उन्होंने कहा कि बीच के कालखंड में इस जनपद को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज यहां की पहचान बन गई है। उन्होंने कहा, गाजीपुर 'माफिया मुक्त' जनपद बना है। विकास की प्रक्रिया के साथ गाजीपुर अब आधुनिक आधारभूत ढांचे का लाभ प्राप्त कर रहा है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तथा गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। आधुनिक आधारभूत ढांचा जनपद गाजीपुर को नई पहचान दिलाएगा।

आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर गाजीपुर में अंधऊ चौकिया बाईपास के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इससे विकास बढ़ेगा और यातायात की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि चितनाथ घाट व कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़े कॉरिडोर निर्माण से संबंधित प्रस्ताव का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पर भी आगे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि विकास का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और राजस्व वादों का गुण-दोष के आधार पर तेजी से निस्तारण भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन भी हैं। उन्होंने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत यहां युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं।

निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी के हमले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि मुख्य विपक्षी दल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बिना किसी सबूत के सवाल उठा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और दावा किया कि इसमें कोई छिटपुट गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि 'वोट चोरी' हुई थी। उन्होंने डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी करने की मांग की थी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 'एक्स' पर मीडिया की एक खबर साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में नागपुर दक्षिण पश्चिम में 29,219 नए मतदाता जुड़े। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही ''लोकतंत्र विरोधी'' और ''आपातकाल समर्थक'' हैं। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा , राहुल गांधी की 90 चुनावी हार को छिपाने के लिए, कांग्रेस पार्टी बिना किसी सबूत के शोर मचाती है और भाग जाती है। सच्चाई है कि जब भी राहुल विफल होते हैं, कांग्रेस या तो मतदाताओं, न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग पर हमला करती है।

अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाराणसी (उप्र)/भाषा। वाराणसी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक संपन्न हो गई। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने यह जानकारी दी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की। शाह सोमवार से ही वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बैठक होटल ताज में हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। परिषद की 24वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को उत्तराखंड में आयोजित की गई थी।

25वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर पोस्ट किया , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' को देश के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बताया है। इसी क्रम में आज वाराणसी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभाग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में बैठक में शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा , बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सीमा सड़क संगठन के माध्यम से अधिक सहयोग का आग्रह किया। साथ ही 'वाइब्रेंट विलेज योजना' के अंतर्गत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार पर अपने विचार रखे।

धामी ने कहा , प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने, 1989 की दूरस्थ घाटी अधिसूचना को निरस्त करने और मानसून के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, अतिवृष्टि व बादल फटने जैसी आपदाओं से सड़कों को होने वाली क्षति के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सुचारू संचालन हेतु राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने की आवश्यकता पर सुझाव दिए। इसी पोस्ट में उन्होंने कहा कि राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि साथ ही नंदा राजजात यात्रा (2026) और 2027 के कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में विकास को नई गति दी : भाजपा की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष

अगरतला/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य ने केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों पर लंबे समय तक पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का मंगलवार को आरोप लगाते हुए क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा , चाहे साक्षरता अभियान हो या सामाजिक-आर्थिक विकास या बुनियादी ढांचे का निर्माण, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया। भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी ने पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर का 70 बार दौरा किया। उन्होंने दावा किया , कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा की। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने शायद ही कभी इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन की बदौलत त्रिपुरा अब मिजोरम के बाद पूर्वोत्तर में दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर बनाया है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

अमेरिकी परामर्श में मेघालय को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ना सही नहीं : संगमा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिलांग/भाषा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका द्वारा जारी यात्रा परामर्श में राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ना गलत है और वह इस मामले को भारत में अमेरिकी राजदूत के समक्ष उठाएंगे।

मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा कि राज्य पर्यटकों के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है।

अमेरिका की सरकार ने हाल में परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से आतंकवाद और हिंसा के कारण मेघालय तथा पूर्वोत्तर के राज्यों की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा था।

इसमें कहा गया है कि यदि कर्मचारी केवल इन राज्यों के राजधानियों की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा , अमेरिकी दूतावास ने मेघालय और पूरे पूर्वोत्तर को पूरी तरह गलत तरीके से पेश किया है। मुझे नहीं लगता कि अधिसूचना सही है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में भारत में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात करेंगे।

संगमा ने कहा , मैं अमेरिकी राजदूत के साथ-साथ गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समक्ष तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

तिनसॉन्ग ने परामर्श के बारे में पूछे जाने पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा , यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने ऐसा परामर्श जारी किया है। हमें नहीं पता कि वे मेघालय को उस श्रेणी में रखने के लिए अपनी जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं।

मेघालय के गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे तिनसॉन्ग ने सुरक्षा और आतिथ्य के मामले में राज्य के रिकॉर्ड का दृढ़तापूर्वक बचाव किया। उन्होंने कहा , मेघालय दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है और राज्य के लोग अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए जाने जाते हैं।

तिनसॉन्ग ने कहा कि जो लोग मेघालय नहीं आए हैं और वहां के लोगों से नहीं मिले हैं, उनके मन में कई तरह के संदेह हो सकते हैं।

उन्होंने कहा , मेघालय घूमने आए लोगों से बात करें और राज्य के खूबसूरत गांवों में रहने वाले मेहनती लोगों से मिलें। ये असली अंबेसेडर हैं।

गोमांस फेंकने का धंधा बंद होना चाहिए, अन्यथा बदले की कार्रवाई हो सकती है : हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गोवालपारा (असम)/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न स्थानों पर गोमांस फेंकने का ''धंधा'' बंद होना चाहिए, अन्यथा अन्य लोग जवाबी कार्रवाई में विभिन्न क्षेत्रों में सूअर का मांस रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो और ऐसे मामलों पर कोई ''झगड़ा'' नहीं होना चाहिए।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंदू धर्म स्थलों और अन्य क्षेत्रों के पास कथित तौर पर 'गोमांस' और गाय के अंग फेंके जाने की हाल की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा , हमें इन लोगों को गोमांस फेंकने के इस धंधे से रोकना होगा, अन्यथा अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर सूअर का मांस रखना शुरू कर देंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि हिंदुओं को एक प्रकार का मांस पसंद नहीं है, तो मुसलमान भी दूसरे प्रकार को पसंद नहीं करते... यदि मंदिरों और नामघरों (वैष्णव पूजा स्थल) के सामने गोमांस फेंका जाता है, तो वे तब क्या करेंगे, जब मस्जिदों के सामने सूअर का मांस रखा जाएगा?''

लालू प्रसाद फिर राजद अध्यक्ष निर्वाचित हुए

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके संस्थापक लालू प्रसाद को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के संगठन चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने यहां प्रेसवार्ता में बताया कि प्रसाद एकमात्र उम्मीदवार थे, जिन्होंने एक दिन पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और जांच के दौरान वह सही पाया गया।

पूर्वे ने कहा , औपचारिक घोषणा पांच जुलाई को यहां की जाएगी, जब पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। परिषद की बैठक में लालू प्रसाद को निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस बीच, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने मुख्य विपक्षी दल पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि प्रसाद के दोबारा निर्वाचित होने से यह साबित हो गया है कि 28 साल पुराने राजद पर ''एक परिवार का नियंत्रण'' है। जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक बयान में आरोप लगाया कि राजद प्रमुख के बेटे और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ''राजनीति में नैतिकता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें और उनके परिवार में नैतिकता का स्पष्ट अभाव नजर आता है।

तीन सपा विधायकों को निष्कासित करके हमने उनका 'टेक्निकल इशू' खत्म किया : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को तंज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने तीन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करके उनके मंत्री बनने में सामने आ रहे 'टेक्निकल इशू' (तकनीकी बाधा) को दूर कर दिया है। यादव ने कहा कि जब वे मंत्री बन जाएंगे तो वह बाकी बागी विधायकों को भी निकालकर उनकी भी बाधा दूर कर देंगे।

यादव ने सपा प्रदेश मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के तीन बागी विधायकों को निष्कासित किए जाने के सवाल पर तंज भरे अंदाज में कहा , असल में उनके सामने एक 'टेक्निकल इशू' था। हमारे विधायक होने की वजह से वे मंत्री नहीं बन पा रहे थे। हमने उस 'टेक्निकल इश्यू' का समाधान किया है। अब वे मंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा , अब आप पूछोगे कि हमने तीन (बागी विधायक) निकाले, बाकी क्यों नहीं निकाले? सबको मंत्री बनना था और सबको आश्वासन मिला था। हमने तीन को निकालकर 'टेक्निकल इश्यू' का समाधान किया है। अब वे मंत्री बन सकते हैं। जब यह तीन मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी 'टेक्निकल इशू' हम 'रिजॉल्व' (हल) कर देंगे, मंत्री बनने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जिम्मेदारी है कि इन्हें (सोमवार को निष्कासित विधायकों को) जल्दी मंत्री बनाएं, तो बाकी लोगों को जब हम हटाएं तो वे भी मंत्री बन जाएं।

सपा के तीन बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय ने पिछले साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर दल से बगावत करते हुए सत्तारूढ़ (भाजपा) के पक्ष में वोट किया था।

इसके अलावा राकेश पांडेय, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने कथित तौर पर भाजपा के पक्ष में 'क्रॉस वोटिंग' की थी। इनके अलावा पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी देवी मतदान से अनुपस्थित रही थीं। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

हिंदू धर्म स्थलों के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार : अजय राय

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि वाराणसी के मूल स्वरूप को बर्बाद करने के बाद भाजपा की नजर वृंदावन की कुंज गलियों और विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर है।

राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा , हिंदुत्व के नाम पर आयी भाजपा सरकार लगातार हिंदू धर्म स्थलों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दुनिया में जितने भी प्राचीन शहर हैं, सबने अपना स्वरूप बचाकर रखा है। वह चाहे मिस्र हो या वेनिस। सिर्फ भाजपा सरकार पुराने सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलों को नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा , पहले वाराणसी के मूल स्वरूप को बर्बाद किया गया। वहां काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के नाम पर सैकड़ों शिवलिंग और मंदिरों को तोड़ा गया, वट वृक्ष काट दिया गया। फिर अयोध्या में अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कभी नहीं होता था।

ओडिशा में मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं : कांग्रेस की तथ्यान्वेषी टीम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। कांग्रेस की तथ्यान्वेषी टीम ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के गृह जिले क्योंझर सहित पूरे ओडिशा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। टीम के मुताबिक हाल के समय में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले सामने आए हैं।

कांग्रेस महासचिव दीपा दासमुंशी के नेतृत्व में पार्टी की पांच सदस्यीय टीम ने ओडिशा के चार जिलों का दौरा किया, जहां हाल ही में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आई थीं। टीम ने गत चार दिन में कंधमाल, गंजम, क्योंझर और मयूरभंज जिलों का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने पीड़ितों के परिवारों, ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस सहित विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा करने के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आश्चर्य व्यक्त किया। टीम की सदस्य और सांसद प्रणीति शिंदे ने यहां प्रेस वार्ता में कहा , प्रत्येक पीड़ित के परिवार से मिलने के बाद, मैं केवल इतना कह सकती हूं कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य ओडिशा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ऐप शुरू किया

भुवनेश्वर/भाषा। रथ यात्रा के दौरान पुरी आने वाले श्रद्धालुओं को रेल सेवाओं की भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने विशेष मोबाइल ऐप 'ईसीओआर यात्रा' शुरू किया। पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह 'एंड्रॉयड' आधारित ऐप 'गूगल प्ले स्टोर' पर उपलब्ध है और त्योहार के दौरान रेल सेवाओं तथा यात्री सुविधाओं की डिजिटल जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप खासतौर पर रथ यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों को समग्र-त्वरित जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। 'ईसीओआर यात्रा' ऐप यात्रियों के लिए एकीकृत डिजिटल समाधान के रूप में कार्य करेगा, जिससे वे अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे, परिवहन सेवाओं तक पहुंच पाएंगे और रेलवे से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अंपायर के फैसले पर असहमति जताने पर पंत को फटकार लगाई

लीड्स/भाषा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ यहां चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के लिए फटकार लगाई है। हेडिंग्ले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पंत को इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान मैदान पर उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई गई। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी को आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन का दोषी पाया गया। आईसीसी ने बयान में कहा , पंत को खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.8 का उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति व्यक्त करने से संबंधित है। इसके अलावा, पंत के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है। यह 24 महीनों में उनका पहला अपराध था।

भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी कर्मचारियों को बनाया जा रहा निशाना : ममता बनर्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य के बांग्ला भाषी लोगों को भाजपा शासित कुछ राज्यों में बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बनर्जी ने विधानसभा कक्ष में संवाददाताओं से कहा कि उनके पास सूचना है कि वैध दस्तावेज दिखाने के बावजूद बांग्ला भाषी 300-400 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में एक इमारत में बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा , क्या रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों की भाषा बांग्ला में बात करना अपराध है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के अलावा ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित दिल्ली और मध्यप्रदेश में भी पहले हो चुकी हैं।

एक सवाल के जवाब में बनर्जी ने कहा कि मुख्य सचिव इस ताजा मुद्दे को राजस्थान में अपने समकक्ष के सामने उठा रहे हैं। नबन्ना(राज्य सचिवालय) के सूत्रों ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर भिवाड़ी में हुई। उन्होंने कहा , जहां तक मेरी जानकारी है, वर्ष 1971 तक जो भी भारत आया वह भारतीय नागरिक है। बनर्जी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के 1.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक बंगाल में विभिन्न इकाइयों में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया , लेकिन हम कभी भी ऐसे कदम उठाने की कल्पना नहीं कर सकते जो भारत की बहुलतावाद की भावना के खिलाफ हो। क्या होगा यदि दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों के खिलाफ उनकी मातृभाषा बोलने पर ऐसे कदम उठाए जाएं? क्या भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलना अपवित्र माना जाता है?'' उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बांग्ला को वैकल्पिक भाषा के रूप में हटा दिया गया है तथा इस कदम पर गहरा खेद व्यक्त किया। बनर्जी ने सवाल किया , क्या अमित शाह के अधीन केंद्रीय गृह मंत्रालय बांग्ला भाषी प्रवासियों के खिलाफ इस अभियान से अनभिज्ञ है?'' मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के लगभग 22 लाख प्रवासी श्रमिक वर्तमान में अन्य राज्यों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा , मैं अक्सर लोगों से यहीं रहकर काम करने का आग्रह करती हूं, लेकिन बहुत से लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में राज्य से बाहर चले जाते हैं। क्या बांग्ला भाषा में बात करना उनका अपराध है? उन सभी के पास नागरिकता संबंधी आवश्यक दस्तावेज हैं।

भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर कथित अत्याचारों को लेकर उन्होंने कहा , यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले हो रहे हैं।

खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने अगरतला में साइ केंद्र का औचक दौरा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। खेल राज्यमंत्री रक्षा खड़से ने मंगलवार को यहां भारतीय खेल प्राधिकरण(साइ) के प्रशिक्षण केंद्र का औचक दौरा करके सुविधाओं का जायजा लिया और खिलाड़ियों की समस्याओं को सुना।

खड़से इस समय सरकार की 'पूर्वोत्तर संपर्क सेतु' संवाद पहल के तहत त्रिपुरा के दौरे पर है।

साइ के खेल प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) के दौरे पर खड़से ने अभ्यास सुविधाओं, कोचों के काम और खिलाड़ियों की प्रगति का जायजा लिया।

मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार , खेल राज्यमंत्री ने एसटीसी केंद्र की अत्याधुनिक सुविधाओं का मुआयना किया।

अगरतला स्थित केंद्र जिम्नास्टिक पर केंद्रित है। खड़से ने केंद्र में अभ्यास उपकरणों, होस्टल सुविधाओं, खिलाड़ियों की खुराक, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा का जायजा लिया। उन्होंने बाद में कहा , भारत का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है। केंद्र सरकार इनके साथ है और इनकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है।

सुविचार

प्रेम के मायने वही समझ सकता है जिसने राधा के दिल की धड़कनों में कृष्ण की धुन सुनी हो।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

युवा शक्ति और उज्ज्वल भविष्य

होसपेट के एमजे नगर में युवाओं के लिए आयोजित सेमिनार में आचार्यश्री विमलसागरसूरी ने जो प्रवचन दिए, वे समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। उनके ये शब्द अत्यंत प्रासंगिक हैं कि 'देश का भविष्य व्यापार-उद्योग, सेना, प्रशासन, जीडीपी की वृद्धि और साधन-सुविधाओं के भरोसे ही उज्ज्वल होगा, ऐसा नहीं है। देश के किशोर और युवा कौनसी राह पर आगे बढ़ते हैं, उस पर भविष्य निर्भर करेगा। किशोर तथा युवा वर्ग राष्ट्र और समाज की रीढ़ हैं।' यह संदेश आज के भौतिकवादी युग में एक गहरी चेतना जगाता है। आज का दौर उपभोग और तात्कालिक सुख की ओर झुका हुआ है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और भौतिक सुखों की दौड़ में अच्छाइयों और नैतिक मूल्यों का स्थान धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। मनुष्य को बुराइयां जल्दी प्रभावित कर रही हैं। अच्छाइयों को अपनाने के लिए तो आत्म-नियंत्रण और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह एक कटु सत्य है कि आज बुराइयों का प्रचार-प्रसार अधिक हो रहा है और यह समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। युवा वर्ग, जो ऊर्जा, उत्साह और नवाचार का प्रतीक है, उसे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। प्रश्न है- अच्छाई को कैसे बढ़ावा दिया जाए? लोग यह तो शिकायत करते हैं कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अखबार, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया ... जहां नजर जाती है, ये ही ज्यादा दिखती हैं। उनका कहना गलत भी नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू को देखें। बेशक बुराइयां बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छाई के समर्थन में खड़े होंगे, तब ही तो उसकी जड़ मजबूत होगी। अच्छे साहित्य और अच्छे सिनेमा की कमी इसलिए है, क्योंकि उन्हें बहुत कम लोगों का समर्थन मिलता है। जिस दिन लोग अच्छाई को बढ़ावा देने में रुचि लेने लगेंगे, उसका पलड़ा अपनेआप भारी हो जाएगा।

आचार्यश्री का यह कथन कि 'अच्छाइयों को जीवित रखने के लिए समाज के संगठित प्रयास जरूरी हैं', हमें सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। केवल धन कमाने या उत्सवों में डूबे रहने से न तो व्यक्ति का कल्याण संभव है और न ही समाज का भला हो सकता है। युवाओं को धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हम अपने युवाओं को सही दिशा दे पा रहे हैं? हम उन्हें केवल कमाई और भौतिक सफलता की दौड़ में धकेल रहे हैं या उन्हें एक संतुलित, मूल्य-आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भी दे रहे हैं? आचार्यश्री का संदेश स्पष्ट है- युवा वर्ग को न केवल आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनाना है, बल्कि उसे ऐसी पीढ़ी के रूप में ढालना है, जो अच्छाइयों को संजोए और बुराइयों का डटकर मुकाबला करे। इसके लिए परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां युवा न केवल तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें, बल्कि नैतिकता, करुणा और आत्म-अनुशासन जैसे गुण भी विकसित करें। आचार्यश्री के प्रवचन हमें यह स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र का भविष्य केवल धन-दौलत से उज्ज्वल नहीं हो सकता। भावी पीढ़ी को चरित्रवान भी बनाना होगा। यह संदेश किसी एक समुदाय या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र एवं मानवता के लिए है। यह हर उस व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए प्रासंगिक है, जो एक बेहतर, मूल्य-आधारित और समृद्ध भविष्य की कामना करता है। इस समय अपने युवाओं को वह शक्ति देनी होगी, जो उन्हें न केवल स्वयं का, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में सक्षम बनाए।

ट्वीटर टॉक

जादूगरी केवल मनोरंजन नहीं, एक प्राचीन और आकर्षक कला है जो पीढ़ियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती आ रही है। आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध जादूगर श्री ओपी शर्मा का शो देखा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मंत्रमुग्ध नजर आए।

-अशोक गहलोत

मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यों/संघ क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का यह सम्मेलन वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

-ओम बिरला

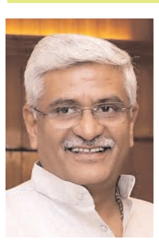

राजस्थान की गर्वीली विरासत को अपने अद्भुत स्थापत्य और संस्कृति से दर्शाने वाली महाधरा बूंदी के 784वें स्थापना दिवस की सभी बूँदीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! ईश्वर की कृपा इस महान नगर पर सदैव विद्यमान रहे।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

तेजवान की कसौटी

अंगिरा ऋषि का शिष्य उदयन अत्यंत तेजस्वी सरल तथा सेवाभावी वृत्ति का था। गुरु ने देखा कि कुछ दिनों से वह आलस्य व अहंकार का शिकार होता जा रहा है। एक दिन ऋषि ने उदयन से कहा, 'वत्स, सामने रखी अंगीठी में झांक कर देखो, कोयला दहकने के कारण कितना तेजवान लग रहा है। इसे चिमटे से निकालकर मेरे सामने रख दो जिससे इसकी तेजस्विता का पास से अवलोकन कर सकूं।' उदयन ने चिमटे से कोयला उठाया और गुरुदेव के पास रख दिया। कुछ ही क्षणों में कोयला अंगारे की जगह राख में बदल गया।

ऋषि ने उदयन को समझाया, 'वत्स, अंगीठी का सबसे चमकदार कोयला जिस प्रकार अग्नि के तेज से विमुख होते ही राख बन गया उसी प्रकार सक्रिय और प्रतिभावान व्यक्ति अभ्यास, स्वाध्याय तथा सक्रियता से विमुख होते ही आलस्य तथा अहंकार का शिकार होकर निस्तेज हो जाता है।' उदयन गुरु जी का आशय समझ गया तथा उसने अहंकार और आलस्य त्याग कर पुनः कर्मठ जीवन बिताना शुरू कर दिया।

सामयिक

गुजरात उपचुनाव की सीट हारने को गंभीरता से ले भाजपा

अशोक भाटिया
मोबाइल : 9221232130

विसावदर की जीत आप के लिए सिर्फ़ गुजरात तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप को एक मज़बूत वापसी की ज़रूरत थी। विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरव भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप खत्म हो गई है लेकिन यह जीत दिखाती है कि जनता हमारे साथ है। यह केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार वापसी है।

पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले नजर न आते हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनको शिद्दत से महसूस किया जाता है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुकाबले पंजाब व गुजरात में कहीं ज्यादा देखा जा रहा था - और वो अकेले नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया सहित उनकी भरोसेमंद पूरी टीम भी वहीं डटी हुई थी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल निकले तो थे विपश्यना के लिए, लेकिन उसके बाद भी पंजाब व गुजरात में ही जमे हुए हैं। पंजाब में रुकने की बड़ी वजह तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार होना है, जिसे जैसे भी संभव हो बचाकर रखना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राजनीति कितना मायने रखती है, पंजाब व गुजरात अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की मौजूदगी सबसे बड़ी मिसाल रही।

यही कारण है कि गुजरात में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए उत्साही संकेत लेकर आए हैं। विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरिट पटेल को करीब 17,554 वोटों से हराया है। भाजपा को यह हार बहुत चुभेगी, क्योंकि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के होमग्राउंड में आप के हाथों करारी शिकस्त मिली है। इसके अलावा, यह राष्ट्रवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों के ऊपर क्षेत्रीय समस्याओं और आकांक्षाओं की जीत का भी संकेत है। दरअसल इस सीट पर पहले भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विधायक भुपेन्द्रभाई गांडुभाई भायाणी पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस वजह से उपचुनाव कराए गए थे। भाजपा को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। विसावदर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी आप के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरिट पटेल को 17,554 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा को इस सीट पर आखिरी बार 2007 में जीत मिली थी और तब से इस सीट पर जीत के लिए पार्टी तरस रही है। इस बार यहां जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आम आदमी पार्टी की सटीक रणनीति और सही उम्मीदवार के चुनाव की वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है।विसावदर सीट पर लगातार दूसरी बार आप की झाड़ू चली है। आम आदमी पार्टी की दोबारा इस सीट पर जीत प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के गुजरात मॉडल को चुनौती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने यहां बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराई है। इस जीत ने साबित कर दिया है कि सही उम्मीदवार और जनता के मुद्दे उठाने का असर चुनावी नतीजों पर नजर आता है। इतना ही नहीं यह इस बात का भी संकेत है कि जनता विकल्प को अपनाने में नहीं हिचक रही है।

गुजरात का रिजल्ट भाजपा के लिए भी एक करारा झटका है। जो दशकों से गुजरात में अजेय मानी जाती रही है। इस जीत ने न सिर्फ आप की साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि यह भी साबित किया कि गुजरात की जनता अब बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। दरअसल विसावदर जूनागढ़ जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। जो लंबे समय तक भाजपा का गढ़ रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया था। हालांकि 2007 के बाद से भाजपा इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी। गोपाल इटालिया ने न केवल इस सीट को वापस हासिल किया। बल्कि भाजपा को उसकी ही ज़मीन पर चारों खाने चित कर दिया।

गौरतलब है कि गुजरात में भाजपा की सरकार पिछले दो दशकों से सत्ता में है। इस दौरान विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए। लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों की कमी आज भी देखी जा सकती है। विसावदर जैसे कृषि-प्रधान क्षेत्र में किसानों की समस्याएं सिंचाई की कमी, फसलों का उचित मूल्य न मिलना। और कर्ज का बोझ भाजपा के लिए मुसीबत बन गईं। गोपाल इटालिया ने इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। और जनता के बीच यह संदेश देने में कामयाब रहे कि आप उनकी आवाज़ बन सकती है। गोपाल इटालिया पहले आप के गुजरात अध्यक्ष रह चुके हैं। एक ज़मीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी सादगी, बेबाकी और जनता से सीधा संवाद उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बना। और उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इसके अलावा आप ने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों के काम मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात की जनता के सामने मॉडल के तौर पर पेश किया। यह रणनीति विसावदर के मतदाताओं, खासकर युवाओं और किसानों के बीच खूब जमी।

वहीं भाजपा के लिए यह हार सिर्फ़ बाहरी कारणों की वजह से नहीं। बल्कि पार्टी के भीतर की गुटबाज़ी और नेतृत्व की कमज़ोरियों ने भी इस हार को और गहरा किया। किरीट पटेल को टिकट देने के फैसले पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी। इसके अलावा भूपेंद्र भायानी के आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने जिस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया। उससे विसावदर की जनता में गुस्सा था। लोगों ने इसे 'दलबदल की राजनीति' के तौर पर देखा और भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया था कांग्रेस कभी गुजरात में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी थी। अब पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है। विसावदर में नितिन रणपरिया की हार और महज 5,501 वोट मिलना कांग्रेस की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस की कमज़ोरी का फायदा सीधे तौर पर आप को मिला क्योंकि जो वोटर भाजपा के खिलाफ़ थे और उन्होंने आप को एक मज़बूत विकल्प के तौर पर चुना। गोपाल इटालिया की यह जीत उनकी मेहनत और आप की रणनीति का नतीजा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गोपाल ने अपनी बेबाकी और ज़मीनी मुद्दों पर पकड़ के दम पर विसावदर की जनता का दिल जीता। और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए जैसे कि भाजपा उम्मीदवार द्वारा शराब बांटने की कोशिश। आप ने इस मामले को सोशल मीडिया पर खूब उछाला जिससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा। विसावदर की इस जीत ने गुजरात की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भाजपा का अजेय किला अब कमज़ोर पड़ रहा है ? क्या आप गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने जा रही है ? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप भाजपा के लिए एक मज़बूत चुनौती पेश कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा। लेकिन यह जीत निश्चित तौर पर 'आप' के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है।

वहीं 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा के पास 161 सीटें थीं। जो अब 162 हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने कड़ी सीट पर जीत हासिल की। लेकिन विसावदर की हार भाजपा के लिए एक चेतावनी है। अगर आप इसी तरह ज़मीनी स्तर पर काम करती रही तो 2027 में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। भाजपा को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। विसावदर की हार के बाद भाजपा के लिए कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पार्टी ने सही उम्मीदवार चुना। क्या स्थानीय मुद्दों को समझने में चूक हुई। क्या दलबदल की राजनीति अब उल्टा पड़ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हार के बाद कहा कि वे इस पर आत्ममंथन करेंगे लेकिन यह साफ़ है कि पार्टी को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आपको बता दें कि भूपेंद्र भायानी का आप से भाजपा में जाना और फिर किरीट पटेल को टिकट देना भाजपा के लिए भारी पड़ गया। जनता ने इसे दलबदल की राजनीति के तौर पर देखा। और इसका जवाब वोट के ज़रिए दिया। यह भाजपा के लिए एक सबक है कि दलबदल कराने की रणनीति हमेशा कामयाब नहीं होती।

भाजपा का प्रचार इस बार उतना प्रभावी नहीं रहा जितना पहले देखा गया था। गोपाल इटालिया ने ज़मीनी स्तर पर घर-घर जाकर प्रचार किया जबकि भाजपा का प्रचार मुख्य रूप से अपनी सरकार के दावों तक सीमित रहा इसके अलावा आप ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया खासकर शराब बांटने के आरोप को वायरल करके।

विसावदर की जीत आप के लिए सिर्फ़ गुजरात तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप को एक मज़बूत वापसी की ज़रूरत थी। विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरव भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप खत्म हो गई है लेकिन यह जीत दिखाती है कि जनता हमारे साथ है । यह केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार वापसी है। वहीं यह जीत आप के लिए 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक मज़बूत आधार तैयार कर सकती है अगर आप इसी तरह ज़मीनी स्तर पर काम करती रही तो वह गुजरात में भाजपा के लिए एक मज़बूत चुनौती बन सकती है। बता दें कि गोपाल इटालिया की विसावदर में जीत न केवल आप की ताकत को दर्शाती है। बल्कि यह भी बताती है कि गुजरात की जनता अब बदलाव के मूड में है। भाजपा के लिए यह हार एक चेतावनी है कि उनकी ज़मीन अब खिसक रही है। अगर पार्टी ने समय रहते अपनी रणनीति में सुधार नहीं किया तो 2027 के चुनाव में उसे और बड़े झटके लग सकते हैं दूसरी ओर आप और गोपाल इटालिया के लिए यह जीत एक नई शुरुआत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप इस जीत को गुजरात में एक बड़े सियासी बदलाव में बदल पाएगी।

नजरिया

आपातकाल : आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

डॉ. आशीष वशिष्ठ
मोबाइल : 94-5100-5200

पचास वर्ष पूर्व आज के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश इस फैसले से भौंचक रह गया। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। आपातकाल लगाया गया, जो मार्च 1977 तक चला। इस दौरान भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया और एक तानाशाही शासन की शुरुआत इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और आम नागरिकों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और हत्या तक की गई। इस दौर में संविधान को भी कमजोर किया गया। हालांकि, आपातकाल का हर पहलू चौंकाने वाला था, लेकिन खासकर छात्रों पर किए गए अत्याचार बेहद निंदनीय थे। सब कुछ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए।

पहली बार ऐसा मौका था जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। लोगों को आपातकाल के मतलब भी नहीं पता था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आम जनता के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। आम जनता, मीडिया समूह, रेडियो, और अन्य प्रचार के माध्यमों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर की प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। आपातकाल की सूचना के बाद से ही देश में ढूंढ-ढूंढ कर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। तत्कालीन समय के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के विपरीत विचारधारा वाले सभी लोगों और आम जनता में बेगुनाहों को भी जेल में भर दिया गया था, जेलों में जगह नहीं बची थी। करीब 1,40,000 लोगों आपातकाल में बिना किसी सुनवाई के राजनीतिक बंदी बनाया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल के दौरान पूरे देश का नियंत्रण गांधी-नेहरू परिवार के हाथ में था। कांग्रेस ने आपातकाल की आड़ में वो सभी काम किए जो ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से अशोभनीय थे बल्कि अमानवीय भी थे। प्रेस में सरकार या आपातकाल की आलोचना करना अपराध की श्रेणी में आ चुका था। प्रेस-मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किया गया था। हालात यह थे कि कांग्रेस समर्थित उस अधिकारी के अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी हो रही थी। यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय विचार और भारतीयता के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल उस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। विरोध के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने गोलियां भी चलाईं। चार लोगों की जान चली गई।

संजय गांधी की सनक के चलते सड़क से भिखारियों, झोपड़पट्टी के लोगों और राहगीरों को पकड़ कर जबरन नसबंदी के टार्गेट पूरे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को नसबंदी अभियान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी थी। जिसमें 42 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। मृतकों की स्मृति में यहां शहीद चौक बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान देशभर में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। 21 महीने के बाद जयप्रकाश का आंदोलन निर्णायक मुकाम तक जा पहुंचा। इंदिरा गांधी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 में आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को जानने के लिए जस्टिस जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन गठित किया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई उस वक्त ना देश में आर्थिक हालात खराब थे और ना ही कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी इच्छा के अनुसार लगाया था और इस संबंध में उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों को छोड़कर किसी भी सहयोगी से कोई विमर्श नहीं किया था।

आपातकाल में गिरफ्तार किए गए अधिकतर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी, जो उन्हें अस्पताल में मौजूद नहीं कराई गई। इंदिरा गांधी की तानाशाही का एक नमूना इस बात से भी पता चलता है कि शाह आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैए की बेहद आलोचना की थी। आयोग ने कहा था कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की जबरदस्ती नसबंदी की गई इसके साथ-ऑटो रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना था कि सरकारी तंत्र का उपयोग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे आपातकाल का इस्तेमाल किया गया।

जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल किया था कि जीने का अधिकार स्थगित है। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र 1 अगस्त 1977 में संसद में पेश किया गया। सत्या सी पेज के श्वेत पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि तानाशाही की इच्छा रखने वाली इंदिरा गांधी ने अपनी अध्यक्षता में तय किया था कि प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन चारों समाचार एजेंसियों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जिससे उन्हें सेंसर करने और संभालने में आसानी होगी।

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता पिछले कुछ समय अक्सर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। संसद से सड़क तक वे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि उनकी पार्टी के नेता ने दादागिरी करके इस देश पर 21 महीने आपातकाल लगाकर लोगों को जेल में ठूंस दिया था। असल में, 1975 में लगाया हुआ आपातकाल इंदिरा गांधी की गलती नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी का अहंकार था। दिसंबर 2024 को सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का उल्लेख किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी यह कलंक मिट नहीं सकेगा क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

महत्त्वपूर्ण
Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

मोदी की पार्टी में शामिल होने का मेरा कोई संकेत नहीं : थरूर

मॉस्को/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' पर वैश्विक पहुंच के संबंध में उनका लेख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पार्टी में शामिल होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के लिए खड़े होने का संदेश है।

थरूर ने अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' के लिए सोमवार को लिखे एक लेख में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऊर्जा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक ''अहम पूंजी'' बनी हुई है, लेकिन इसे अधिक सहयोग एवं समर्थन की जरूरत है।

उनकी टिप्पणियों को कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से असहज स्थिति पैदा करने और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में दरार पड़ने के आसार के तौर पर देखा गया।

यहां एक कार्यक्रम में लेख के बारे में पूछे जाने पर तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा , यह प्रधानमंत्री की पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का मेरा संकेत नहीं है, जैसा कि कुछ लोग दुर्भाग्यवश कह रहे हैं। यह राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित और भारत के लिए खड़े होने के लिए एक बयान है, जो मेरे विचार से मूल रूप से यही कारण है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में 25 साल की सेवा के बाद भारत वापस आया। थरूर ने कहा , मैंने भारत की सेवा के लिए ऐसा किया और मुझे ऐसा करने का अवसर पाकर बहुत गर्व है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह लेख 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कूटनीतिक संपर्क अभियान की सफलता का वर्णन किया था। थरूर ने कहा , लोग हमेशा इन सब बातों को आज की खबरों के संदर्भ में देखते हैं। यह एक ऐसा लेख है जिसमें मैंने इस संपर्क अभियान की सफलता का वर्णन किया है, जिसने अन्य बातों के अलावा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के मामले में सभी दलों की एकता को प्रदर्शित किया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा , इसलिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अन्य देशों के साथ बातचीत में बहुआयामी व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में अधिक देशों की यात्रा की है और ऐसा उन्होंने भारत के संदेश को दुनिया भर में ले जाने के लिए किया है। उन्होंने कहा , और मेरे विचार से, हम सभी ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों, पृष्ठभूमियों, समूहों, धर्मों की शक्ति का उपयोग करके उनके प्रयासों को समर्थन दिया और दुनिया को यह संदेश दिया कि एकजुट भारत किस लिए खड़ा है।

थरूर ने कहा , आज यह आतंकवाद के खिलाफ संदेश है, कल यह किसी और विषय पर संदेश हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। थरूर ने यह भी कहा , मेरी लंबे समय से राय रही है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज नहीं है, केवल भारतीय विदेश नीति और भारतीय राष्ट्रीय हित ही है।

थरूर ने कहा , मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने यह कई साल पहले कहा था और मैंने यह सार्वजनिक रूप से, रिकॉर्ड पर, पहली बार तब कहा था जब मैं 2014 में विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष बना था।

थरूर ने अपने लेख में कहा कि ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बाद किया गया कूटनीतिक संपर्क अभियान राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी संवाद का क्षण था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर थरूर के इस लेख को साझा किया।

जन्मदिन

कोलकाता में युवा अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का जन्मदिन मनाते हुए समर्थक।

भारत तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एशिया में लोकतंत्र के लिए 'आदर्श' : सिंघवी

टोक्यो/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने मंगलवार को कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत एशिया में लोकतंत्र और विकास के लिए 'आदर्श' के रूप में उभरा है।

यहां संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू) में भारतीय लोकतंत्र पर मुख्य व्याख्यान देते हुए चार बार के सांसद और प्रख्यात विधिवेत्ता सिंघवी ने कहा कि सच्चा विकास सकल घरेलू उत्पाद से नहीं बल्कि सम्मान से शुरू होता है और यदि यह सबसे कमजोर लोगों को पीछे छोड़ देता है तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। सिंघवी ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सशक्त अभिव्यक्ति की तथा साम्राज्यवाद-विरोधी राष्ट्रों के बीच विश्व के सबसे बड़े तथा सर्वाधिक स्थायी लोकतंत्र के रूप में इसकी स्थिति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत के जीवंत लोकतंत्र की तुलना अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कई देशों के सामने मौजूद संवैधानिक चुनौतियों से करते हुए भारत के लचीलेपन, बहुलवाद और इसकी संस्थाओं की संरचनात्मक मजबूती को रेखांकित किया। सिंघवी को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने यूएनयू के रेक्टर प्रोफेसर शिलिदजी मारवाला द्वारा संचालित सत्र में उपस्थित प्रतिष्ठित लोगों को संबोधित किया। शिलिदजी मारवाला जोहानिसबर्ग विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा विल्सन कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में शोधकर्ता रह चुके हैं।

मुलाकात

अभिनेता और फिल्म निर्माता सुनील शेट्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मंगलवार को मुंबई के राजभवन में मुलाकात की।

अमिताभ बच्चन ने बताया जीवन में 'संस्कार' का महत्व

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने माता-पिता तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के दिए गए 'संस्कारों' के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता ने जो अच्छी सीख और मूल्य उन्हें सिखाए, वह उनके लिए बहुत कीमती विरासत हैं। अमिताभ मानते हैं कि इन संस्कारों की वजह से ही वह आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में 'संस्कार' के बारे में बात की। उन्होंने लिखा, ''हिंदू परंपरा में 'संस्कार' का मतलब होता है, वो खास रीति-रिवाज और विधियां, जो इंसान के जीवन में अलग-अलग मौकों पर की जाती हैं। इनका मकसद इंसान के शरीर, मन और सोच को शुद्ध करना और उनके अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व को बनाना होता है।''

उन्होंने कहा कि संस्कार किसी इंसान के स्वभाव, सोच और व्यवहार को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यह संस्कार उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने, सही और गलत में फर्क समझने, और ईमानदारी से जीने की सीख देते हैं। अमिताभ ने कहा, ''संस्कार एक तरीका है जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं और विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे समाज में एकता बनी रहती है और हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहती हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि संस्कारों की वजह से डर कम होता है, मन मजबूत होता है और जीवन को हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जीने की ताकत मिलती है। महानायक ने कहा कि उनके माता-पिता ने संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा, ''हमारे जीवन में, खासकर बचपन के दिनों में, मां और बाबूजी ने हमेशा संस्कारों को बहुत महत्व दिया। यह एक सुंदर गुण है, जो हमारे अंदर बचपन से डाला गया।''

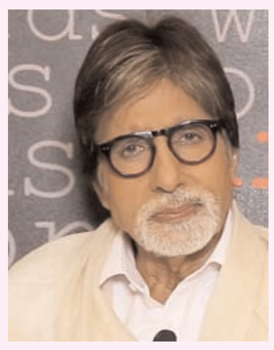

'जुग जुग जियो' के 3 साल पूरे होने पर कियारा आडवाणी ने जताई खुशी

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म 'जुग जुग जियो' को रिलीज हुए तीन साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस ने खुशी जताई और इसे खास अंदाज से सेलिब्रेट किया। कियारा ने फिल्म को अपनी जिंदगी का एक खुशियों भरा और यादगार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से उन्हें मुस्कुराहट, सीखने का मौका और कई अच्छे पल मिले। मंगलवार को, कियारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म से जुड़े डूडल फोटो को शेयर किया, जिसमें फिल्म के चारों मुख्य कलाकार वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर को कार्टून अवतार में दिखाया गया।

एक्ट्रेस ने लिखा, 3 साल इस खूबसूरत फिल्म के, सबसे अच्छी टीम... सबसे मजेदार समय... 'जुग जुग जियो'! उन्होंने इस पोस्ट में

फिल्म के अपने सभी को-स्टार्स को भी टैग किया। 'जुग जुग जियो' 24 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 'जुग जुग जियो' एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे राज मेहता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और वायाकॉम18 स्टूडियोज ने मिलकर बनाया था। फिल्म में मनीष पॉल और यूट्यूबर प्राजक्ता कोली भी अहम किरदार में नजर आए। वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'वॉर 2' की तैयारी कर रही हैं। यह एक एक्शन से भरपूर एंटरटेनर फिल्म है। इस फिल्म में कियारा के साथ दो बड़े सितारे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं।

फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, खबर है कि वह मीना कुमारी की बायोपिक 'कमल और मीना' में भी नजर आ सकती हैं। सूत्रों की मानें तो कियारा को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। हाल ही में कियारा की तेलुगू फिल्म 'गेम चेंजर' रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ साउथ के मशहूर एक्टर राम चरण नजर आए थे।

रणदीप हुड्डा का दिखा नया अवतार, फैंस हैरान

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपना नया लुक शेयर किया है। ऐसा लुक जिसे देख फैंस हैरान हैं। अभिनेता ने अपने नए लुक की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। तस्वीर में एक्टर आधे गंजे नजर आ रहे हैं। उनके सिर पर दोनों साइड तो बाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच से बाल गायब हैं, साथ ही एक्टर की हेयरलाइन भी पीछे जाती हुई नजर आ रही है। पोस्ट को देखकर फैंस भी काफी हैरान हो रहे हैं। पोस्ट शेयर कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'इस मंगलवार के लिए कौन-सी चाय? सिर्फ कॉफी ही नहीं है, जो बन रही है!' सूत्रों के मुताबिक, यह नया लुक हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट के ट्रायल से है, जिसकी शूटिंग रणदीप जल्द ही शुरू करने वाले हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो

अभिनेता हाल ही में फिल्म स्टार सनी देओल की हाई एक्शन फिल्म 'जाट' में विलेन का रोल निभाते दिखे। फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी ने निर्देशित किया है। इसमें सैयामी खेर, रेजिना कैसांद्रा, जगपति बाबू, राम्या कृष्णन, विनीत कुमार सिंह, प्रशांत बजाज, जरीना वहाब, पी. रविशंकर और बबलू पृथ्वीराज थे। हुड्डा जल्द ही हॉलीवुड फिल्म मैचबॉक्स में नजर आने वाले हैं, जिसका निर्देशन सैम हार्ग्रेव कर रहे हैं। फिल्म में जॉन सीना, जेसिका बील, सैम रिचर्डसन, आर्टुरो कास्त्रो, टेयोना पैरिस, दानई गुरिरा और कोरी स्टोल सरीखे कलाकार हैं। मैचबॉक्स 2026 में रिलीज होगी। हिंदी सिनेमा की बात करें तो उनके पास युद्ध ड्रामा ऑपरेशन खुकरी है। इसे एक रियल वॉर ड्रामा पर आधारित बताया जा रहा है। फिल्म 2000 में पश्चिमी अफ्रीका के एक देश में हुए वास्तविक सैन्य अभियान पर आधारित है, जहां भारतीय सेना के 233 जवानों को विद्रोही बलों ने बंधक बना लिया था। यह मिशन भारतीय सेना द्वारा अब तक किए गए सबसे खतरनाक और साहसिक अभियानों में से एक माना जाता है। फिल्म में रणदीप हुड्डा मेजर जनरल राज पाल पुनिया की भूमिका निभाएंगे, जो उस वक्त 14वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के कंपनी कमांडर थे और इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे।

इंडो-इटालियन डीवा जॉर्जिया एंड्रियानी एक बार फिर एक प्रमुख म्यूज़िक लेबल के साथ नए गाने में नज़र आएंगी?

मुंबई/एजेन्सी

जॉर्जिया एंड्रियानी ने हिंदी गानों और संगीत के प्रति अपने प्यार को कभी नहीं छिपाया है, और उन्होंने कई बार यह स्वीकार किया है कि भारत के सिनेमा और मनोरंजन जगत के प्रति उनके प्रेम ने ही उन्हें कुछ साल पहले अपना सब कुछ समेट कर भारत आने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मनोरंजन जगत में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु एक्शन-कॉमेडी सीरीज़ 'कैरोलाइन कमाक्षी' में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाकर की। इसके बाद उन्होंने 'नॉन-स्टॉप धमाल' और 'मार्टिन' जैसी फिल्मों में विशेष गानों के ज़रिए खुद को स्थापित किया और अपनी प्रतिभा तथा परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। अब एक बार फिर मनोरंजन के लिए तैयार, खबरों के मुताबिक जॉर्जिया ने कथित तौर पर इंडस्ट्री के एक प्रमुख संगीत लेबल के साथ एक और गाना साइन किया है। यह गाना वही सब कुछ लेकर आ रहा है जिसके लिए जॉर्जिया जानी जाती हैं दिलकश बोल, कर्णप्रिय धुन और दमदार डांस मूव्स। जॉर्जिया के कुछ

चर्चित डांस नंबर्स जिसमें मीका सिंह के साथ 'रूप तेरा मस्ताना' और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में 'दिल जिससे ज़िंदा हैं' शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी।

यह नया गाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। विभिन्न शैलियों को अपने अंदाज़ में पेश करने की क्षमता ने उन्हें उनकी समकालीन कलाकारों से अलग पहचान दिलाई है। जबकि उनके पहले के गाने और डांस नंबरों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, उनके नवीनतम प्रोजेक्ट को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है जो जॉर्जिया के करियर की दिशा बदल सकता है।

मुलाकात

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अभिनेता और फिल्म निर्माता आमिर खान से मुलाकात की।

आमिर खान स्टारर 'सितारे ज़मीन पर' ने भारतीय बाजार में पहले वीकेंड में करीब 60 करोड़ की कमाई की

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड स्टार और फिल्मकार आमिर खान की फिल्म 'सितारे ज़मीन पर' ने भारतीय बाजार में पहले वीकेंड के दौरान तीन दिनों में करीब 60 करोड़ की कमाई कर ली है। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुयी है। यह फिल्म वर्ष 2007 की क्लासिक तारे ज़मीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल कही जा रही है। इस फिल्म के जरिये आमिर खान ने लंबे समय बाद फिल्मों में कमबैक किया है। फिल्म 'सितारे जमीन पर' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है।

हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'सितारे जमीन पर ' ने पहले दिन भारतीय बाजार में 10.7 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 20.2 करोड़ की कमाई की।

वहीं, अब तीसरे दिन कलेक्शन भी सामने आ गया है। सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार फिल्म सितारे जमीन पर ने तीसरे दिन 29.22 करोड़ का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म सितारे जमीन पर भारतीय बाजार में अपने पहले वीकेंड के दौरान तीन दिनों में करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। फिल्म सितारे जमीन पर में 10 नए चेहरों की धमाकेदार लॉन्चिंग हुयी है। आमिर खान प्रोडक्शंस प्रस्तुत इस फिल्म में 10 राइजिंग सितारे अरूष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, सम्वित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेंडसे, ऋषि शाहानी, ऋषभजैन, नमन मिश्रा और सिमरन मंगेशकर हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'सितारे जमीन पर' में आमिर खान और जेनेलिया देशमुख लीड रोल में हैं। इस फिल्म के गाने अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और संगीत शंकर-एहसान-लॉय ने दिया है। इसका स्क्रीनप्ले दिव्य निधि शर्मा ने लिखा है। इस फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने रवि भागचंदका के साथ प्रोड्यूस किया है, जबकि निर्देशन आर. एस. प्रसन्ना ने किया है।

'हेरा फेरी 3' परेश रावल के बिना अधूरी : सोनाक्षी सिन्हा

मुंबई/एजेन्सी

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सोनाक्षी का मानना है कि अपकमिंग फिल्म में अभिनेता परेश रावल के बिना मजा नहीं है। वह 'बाबूराव गणपतराव आप्टे' के बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। परेश रावल ने 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइज में बाबूराव गणपतराव आप्टे का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था। सोनाक्षी का कहना है कि कॉमेडी फिल्म परेश रावल के बिना अधूरी है। सोनाक्षी ने एक दर्शक के तौर पर कहा, मैं 'हेरा फेरी 3' की परेश रावल के बिना कल्पना भी नहीं कर सकती। उनकी मौजूदगी इस फिल्म की जान है।

हाल ही में परेश रावल ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने पोस्ट में स्पष्ट करते हुए बताया कि 'हेरा फेरी 3' से उनके हटने का फैसला रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था। निर्देशक प्रियदर्शन के साथ भी उनका कोई मनमुटाव नहीं है। उनकी इस घोषणा ने फैंस को निराश किया, क्योंकि बाबूराव का किरदार इस फिल्म की पहचान है।

सोनाक्षी ने अपनी नई फिल्म 'निकिता रॉय' में परेश रावल के साथ पहली बार काम करने के अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने बताया, परेश रावल जैसे शानदार एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उनके काम और अभिनय की गहराई ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब उनसे पूछा गया कि वह परेश रावल को कॉमेडी किरदारों में ज्यादा पसंद करती हैं या गंभीर किरदारों में, तो सोनाक्षी ने कहा, वह हर किरदार में कमाल करते हैं, चाहे वह कॉमेडी हो या गंभीर रोल। उनके लिए कोई एक चुनना मुश्किल है। सोनाक्षी की नई फिल्म 'निकिता रॉय' में वह परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहैल नायर के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म के साथ उनके भाई कुश सिन्हा बतौर निर्देशक शुरुआत करने जा रहे हैं। यह फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

RNI No. 58061/93. Regn No.: NP/KA/BGS/2050/2018-2020 Posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026.

आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जयंती पर गूंजी 'यादें महाप्रज्ञ की'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । तेरापंथ युवक परिषद, विजयनगर द्वारा सोमवार को साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी की 106वीं जयंती के मौके पर भक्ति संध्या यादें महाप्रज्ञ जी की' आयोजन एमसी लेआउट में पोखरणा निवास पर हुआ। इस मौके पर साध्वी संयमलता जी ने आचार्यश्री के तप, ज्ञान और करुणा से भरे जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करने का आह्वान किया। तेयुप के अध्यक्ष कमलेश चोपड़ा ने सभी का स्वागत किया।

भजन गायक ऋषि दुगड़ सहित विजय स्वर संगम टीम आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में निधि चावत, नमन चावत, प्रकाश गाँधी, राकेश दुधोड़िया, सम्पत चावत, प्रेम भंसाली, महेंद्र टेबा, टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिम्मत मांडोत, उपासक अरविन्द मांडोत ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में तेरापंथी सभा, महिला मंडल, प्रोफेशनल फोरम, प्रेक्षा फाउंडेशन एवं अणुव्रत समिति सहित तेयुप के सदस्यों का सहयोग मिला। दिनेश पोखरणा ने सभी को धन्यवाद दिया और विकास बांठिया ने संचालन किया।

जीतो जेबीएन-वी कनेक्ट(जैन बिजनेस नेटवर्क) की बैठक जीतो नार्थ कार्यालय में लेडीज विंग की कोषाध्यक्ष व जेबीएन संयोजिका तनुजा मेहता तथा संयुक्त सचिव सुमन रांका की उपस्थिति में हुई।

जेबीएन-वी कनेक्ट रेफरल समूह की बैठक आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो जेबीएन-वी कनेक्ट(जैन बिजनेस नेटवर्क) की बैठक जीतो नार्थ कार्यालय में लेडीज विंग की कोषाध्यक्ष व जेबीएन संयोजिका तनुजा मेहता तथा संयुक्त सचिव सुमन रांका की उपस्थिति में हुई। बैठक की मुख्य वक्ता शुभम मेडिकल्स और जनरल स्टोर्स की संस्थापिका लीला पितलिया ने वन जेबीएन एप्प की जानकारी प्रस्तुत की। यह ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जेबीएन समुदाय के भीतर नेटवर्किंग, रेफरल और व्यावसायिक विकास को सरल और सशक्त बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। रेफरल हेड मीना जैन, रेफरल लीड लीला पितलिया तथा रेफरल सचिव सीए सुखदेवी जैन ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्याओं को अपनी 30-सेकंड की व्यावसायिक पिच प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ 30 सेकंड की पिच के लिए दीपिका जैन, सबसे अधिक रेफरल देने के लिए सुशीला श्रीश्रीमाल तथा सबसे अधिक व्यवसाय देने के लिए निकिता जैन को सम्मानित किया गया।

आपातकाल की यादें आज भी रूह कंपा देती हैं : कोश्यारी

देहरादून/भाषा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को कहा कि आपातकाल के समय जेल में रहने के दौरान उन्हें अनेक यातनाएं झेलनी पड़ीं और उस दौर की यादें आज भी उनकी रूह को कंपा देती हैं।

कोश्यारी ने आपातकाल की 50वीं बरसी की पूर्व संध्या पर अपने संघर्षों और अनुभवों को साझा करते हुए 'पीटीआई-वीडियो' से कहा कि उस दौरान वह पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ सीमांत क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लिए कार्य कर रहे थे और कुछ महीने पहले शुरू किए अपने अखबार के माध्यम से पहाड़ों में सरकार के ख़िलाफ आवाज़ उठा रहे थे।

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो उन्हें भी अपनी गिरफ़्तारी की आशंका हो गई थी। उन्होंने बताया, रात के लगभग 11 बजे तेज बारिश हो रही थी। मेरे मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाकर बताया कि पुलिस मुझे पकड़ने आई है। मैं समझ चुका था कि अब मेरी गिरफ़्तारी तय है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्हें अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया जहां उन्हें और उनके साथियों को कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ीं। कोश्यारी ने बताया, खाने में चावल में कीड़े पड़े होते थे। मेरे भाई को मुझसे मिलने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा , आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और एकाध अखबारों को छोड़कर सभी अखबार सरकार के पक्ष में लिखते थे।

भाजपा नेता कोश्यारी ने कहा कि उस समय लोगों में असंतोष व्याप्त था और आरएसएस तथा जनसंघ ने जनता को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, जेल में सभी पार्टियों के नेता एकसाथ बंद थे। संघ के वरिष्ठ अधिकारी चोरी-छिपे आकर बंदियों से मिलते और उन्हें हौसला देते थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या आज की राजनीति में फिर से आपातकाल जैसी स्थिति संभव है, कोश्यारी ने कहा कि अब संघ और भाजपा के रहते ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सरजापुर बिक्कनहल्ली में भी 27 को निकलेगी प्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । शहर के सरजापुर के बिक्कनहल्ली मैन रोड पर निर्मित जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा के तीन रथों के साथ पहली बार रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह जगन्नाथ मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव और समर्पण का उदाहरण है। मंदिर की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। इस मंदिर में स्थानीय कन्नड़ और अन्य समुदायों के साथ ओडिया भक्त जुड़े हुए हैं। समिति के पदाधिकारी इस पहली रथ यात्रा को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। आयोजकों ने सभी भक्तों को इस रथ यात्रा में शामिल होने का निवेदन किया है।

राजाजीनगर में आयोजित 'एक शाम, महाप्रज्ञ के नाम' धम्मजागरण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के राजाजीनगर स्थित प्राइड पवेलियन में मुनि डॉ श्री पुलकित कुमार जी के सान्निध्य में तेरापन्थ धर्म संघ के दशम आचार्य महाप्रज्ञजी की 106वीं जयंती के मौके पर एक शाम महाप्रज्ञ के नाम' धम्मजागरण का आयोजन किया गया। मुनिश्री ने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञजी आध्यात्म जगत के महान पुरोधा थे जिन्होंने न केवल धर्मसंघ के लिए अपितु मानव जाति के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे अवदान दिए जो सैकड़ों वर्षों तक वंदनीय एवं अनुकरणीय भी रहेंगे। मुनिश्री आदित्य कुमार जी ने गीतिका के माध्यम से भावांजलि अर्पित की। रेणु कोठारी, तेयुप की भजन मंडली प्रज्ञा संगीत सुधा के ललित सेठिया एवं आदित्य मांडोत ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। गांधीनगर सभा के मंत्री विनोद छाजेड़ के निवास स्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजाजीनगर सभा के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सबका स्वागत किया ।विनोद छाजेड़ ने बताया कि मुनिश्री का चातुर्मासिक प्रवेश 6 जुलाई को कुमारा पार्क रोड स्थित कन्हैयालाल गिड़िया के निवास से निकल कर विशाल रैली के साथ गांधीनगर सभा भवन में होगा। उसी दिन रात्रिकालीन धम्मजागरण पैलेस ग्राउंड के प्रिंसेस श्राइन सभागार में हुआ। इस अवसर पर गांधीनगर सभा के अध्यक्ष पारसमल भंसाली, कोषाध्यक्ष प्रकाश कटारिया, संगठन मंत्री राजेंद्र बाफना, युवक परिषद के अध्यक्ष विमल धारीवाल आदि अनेक जन उपस्थित थे। दिनेश छाजेड़ ने धन्यवाद दिया।

प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गाजा में चल रहे तनाव को लेकर इजरायल का विरोध करते, फिलिस्तीन के दोस्तों के बैनर तले फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पोस्टर पकड़े हुए हैं।

आपातकाल एक भयावह भूल और सबसे काला दौर था: विधि विशेषज्ञ

नई दिल्ली/भाषा। देश में 25 जून, 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा एक 'भयावह भूल' थी और आजादी के बाद के भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिहाज से यह 'सबसे काला दौर' था। प्रख्यात विधि विशेषज्ञों ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल की 21 महीने की अवधि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक 'गंभीर घटना' थी और इसका देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा , आपातकाल एक भयावह भूल थी। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि संवैधानिक शक्ति को कभी भी व्यक्तिगत नहीं बनाया जाना चाहिए।

यह हमारे वर्तमान शासकों के लिए भी एक संदेश है। अत्याचार अभिशाप है। भारत के लोग इसके खिलाफ खड़े हुए और वे हमेशा खड़े रहेंगे।

संवैधानिक और कानूनी मामलों के मशहूर विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि 1975 के आपातकाल का एक राजनीतिक और न्यायिक आयाम था।

वर्ष 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक के मुकाबले चार के बहुमत से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखा था।

भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ए. एन. रे और न्यायमूर्ति एम एच बेग, न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एन भगवती के बहुमत के फैसले ने माना कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय मांगने का अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया गया था।

एकमात्र असहमति जताने वाले न्यायमूर्ति एच आर खन्ना ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है और यह केवल संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामले में 1975 का फैसला एडीएम जबलपुर के फैसले से पहले आया था।

'होनहार व संस्कारवान बच्चे परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ाते हैं'

राजाजीनगर में ज्ञानशाला सेमिनार आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के तेरापंथ भवन राजाजीनगर में ज्ञानशाला सेमिनार का आयोजन मुनि डॉ पुलकित कुमार जी के सान्निध्य में किया गया जिसमें मुनिश्री ने कहा कि जिस तरह बीज को जैसी जमीन और वातावरण मिलता है वैसा ही वह फलवान बनता है ठीक उसी तरह बच्चों को जैसे संस्कार मिलते है वैसे ही वे विकास करते है। हमारी संस्कृति-हमारे संस्कार' विषय पर मुनिश्री ने कहा कि बीज बोना आसान है पर संस्कार रूपी खाद-पानी देना भी बेहद जरूरी है। आचार्यश्री महाश्रमण जी भी ज्ञानशाला के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते हैं क्योंकि बच्चे होनहार व संस्कारवान बनकर परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ाते हैं।

ज्ञानशाला के अनेक बच्चों ने कंठस्थ ज्ञान स्तुति, शक्र स्तुति, लोगस्स पाठ, तुलसी अष्टम अवधि आदि की प्रस्तुति दी। आदित्य मुनि जी ने 'घर घर जागे सद संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार' गीत के माध्यम से प्रेरणा दी। ज्ञानशाला सेमिनार में कर्नाटक आंचल के संयोजक मानक संचेती, राजाजीनगर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया वंदना कोठारी ने धन्यवाद दिया। संचालन ज्ञानशाला संयोजिका चेतना वेदमुथा ने किया। ज्ञानार्थी बच्चों को रोशनलाल कोठारी परिवार की तरफ से पारितोषिक वितरित किए गए। शिशु संस्कार बोध ज्ञानार्थी बच्चों का सम्मान किया गया।

कनिष्क विमान बम धमाके की बरसी हिंसक उग्रवाद से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाती है : कार्नी

ओटावा/भाषा

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि 40 वर्ष पहले एअर इंडिया की उड़ान 182 कनिष्क में हुआ बम धमाका ''हिंसक उग्रवाद से लड़ने और कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।

कार्नी की यह टिप्पणी कनिष्क बम धमाके की 40वीं बरसी के अवसर पर आई है। इस घटना को लेकर सोमवार को पूरे कनाडा में समुदाय के सदस्यों, भारतीय मिशन तथा अन्य लोगों द्वारा, यहां डॉव झील स्थित एअर इंडिया स्मारक सहित अन्य स्थानों पर स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। कनाडा के मॉन्ट्रियल से ब्रिटेन के लंदन के रास्ते नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की 'कनिष्क' उड़ान संख्या 182 में 23 जून 1985 को ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया था। इस आतंकवादी हमले में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। कार्नी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा , 40 वर्ष पहले, कनाडा ने अपने इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमले का सामना किया था। आज, हम एअर इंडिया बम धमाके के 268 कनाडाई पीड़ितों और आतंकवादी कृत्यों में मारे गए सभी लोगों को याद करते हैं। यह (घटना) हिंसक उग्रवाद से लड़ने और कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाती है।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भी 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा , यह आतंकवादी हमला हमारे देश के इतिहास में सबसे घातक है - जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम पीड़ितों को याद करते हैं और हमारी संवेदनाएं उनके प्रियजनों के साथ हैं जो दशकों से शोकाकुल हैं। कनाडा आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खतरों और प्रभावों का पता लगाने, रोकने और उनका जवाब देने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। इससे पहले, कार्नी ने एक बयान में कहा कि कनाडा की नई सरकार आतंकवाद के खिलाफ ''स्पष्ट रूप से'' खड़ी है। उन्होंने 40 साल पहले एअर इंडिया की उड़ान 182 कनिष्क पर हुए आतंकी हमले को ''देश के इतिहास का सबसे घातक हमला'' करार दिया था।

ओटावा में सोमवार को एअर इंडिया विमान धमाके की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर डॉव झील स्थित एअर इंडिया स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीड़ितों के परिवारों, मित्रों और अन्य समुदाय के सदस्यों ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया।

इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में एअर इंडिया पीड़ित परिवार संघ के निदेशक सुशील गुप्ता शामिल थे। इस घटना के समय गुप्ता मात्र 12 साल के थे और उन्होंने इस विस्फोट में अपनी मां को खो दिया था।

कनाडा स्थित भारतीय मिशनों ने भी ओटावा और टोरंटो में कार्यक्रम आयोजित किए। ओटावा में कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मय नाइक ने उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बयान में उच्चायोग ने इन पीड़ितों को ''कायरतापूर्ण आतंकवादी बम विस्फोट'' का शिकार बताया।

टोरंटो में कार्यवाहक महावाणिज्यदूत कपिध्वज प्रताप सिंह ने इटोबिकोक के हम्बर बे पार्क में एअर इंडिया 182 स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर इस घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच, सीबीसी न्यूज ने ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस के हवाले से बताया कि 'मिस्टर एक्स' के नाम से जाना जाने वाला एक संदिग्ध के बारे में माना जाता है कि उसने 1985 के एअर इंडिया आतंकवादी हमले में मदद की थी लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं होने का हवाला देते हुए संदिग्ध की पहचान उजागर नहीं की है।

नाटो के ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए जुट रहे वैश्विक नेता, दिशा होगी तय

द हेग (नीदरलैंड)/एपी। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' के ऐतिहासिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वैश्विक नेता नीदरलैंड की राजधानी द हेग में जुट रहे हैं। इस सम्मेलन में तय होगा कि रक्षा व्यय में वृद्धि को लेकर संगठन के 32 सदस्य सहमति की ओर बढ़ते हैं या विभिन्न मुद्दों पर दरार और गहरी होती है। सहयोगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत अपनी सुरक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य का समर्थन करें, ताकि बाहरी हमलों से बचाव के लिए गठबंधन की योजनाओं को पूरा किया जा सके। अमेरिका के शासनाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मुख्य मुद्दा यह होगा कि अमेरिका कैसे सुरक्षा गठबंधन में अन्य देशों से ऐतिहासिक सैन्य खर्च बढ़ाने पर सहमति प्राप्त करता है।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.)
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com